▪ वर्ष-17 ▪ अंक-66 ▪ पृष्ठ-8 ▪ मूल्य : 1 रुपए

नई दिल्ली, गुरुवार, 27 मार्च, 2025

newdibyabharat@gmail.com

अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का... पृष्ठ-3

दिव्य भारत

| राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक |

मानसून सत्र को ई विधानसभा के रूप में आयोजित करने का... पृष्ठ-7

मुगलों से नहीं, छत्रपति शिवाजी से है आगरा की पहचान : योगी

आलोक पाण्डेय

आगरा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आगरा में आयोजित जनपदीय विकास उत्सव में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश सरकर की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के तहत राज्य में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया, जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और 635 करोड़ रुपये की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में योगी सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को दशार्ने वाली एक झलक रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं बल्कि ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल और राधा रानी से है। आगरा की पहचान अगर किसी से है, तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज से है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी आगरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है ये किसी मुगलों से जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल और राधा रानी से है। आगरा की पहचान अगर किसी से है, तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज से है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आगरा में एक म्यूजियम का निर्माण शुरू किया था और उसका नाम मुगल म्यूजियम रखा था। सीएम योगी ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा आखिर मुगलों का आगरा से क्या संबंध है? सीएम योगी ने कहा कि मेरी सरकार ने इस म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया और इसके भव्य स्मारक के निर्माण की कार्ययोजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास दोनों को प्राथमिकता दे रही है। हमने आगरा में पेठा और लेदर इंडस्ट्री को नई पहचान दी है, वहीं बटेश्वर को वैश्विक पटल पर लाने का काम भी डबल इंजन सरकार कर रही है।

- **8 वर्षों ने उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ये 8 वर्ष उत्कर्ष के वर्ष हैं**
- **2017 से पहले का उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी और माफियागिरी का बोलबाला था**
- **विकास कार्यों में बैरियर बन रहा है विपक्ष, इन्हें विकास पसंद नहीं, फैला रहे अफवाह**
- **यूपी अब बीमारू राज्य से देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन गया है**
- **आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे नेटवर्क, हाईवे और एयरपोर्ट हैं**

सीएम योगी ने 2017 से पहले की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उस दौर की अराजकता को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्हें 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश याद होगा। उस समय अराजकता, गुंडागर्दी और माफियागिरी का बोलबाला था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, गरीब भूख से मरता था, व्यापारी और बेटियां असुरक्षित थीं। पर्व-त्योहारों से पहले लोगों के मन में डर रहता था कि कहीं दंगे न हो जाएं, कर्फ्यू न लग जाए। सीएम योगी ने कहा कि उस समय सड़कों पर गड्ढे, शाम होते ही अंधेरा और हर तीसरे दिन दंगों की खबरें उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थीं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यह पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग थे, जो आज झूठ का पुलिंदा लेकर अनर्गल प्रलाप करते हैं।

उन्होंने कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब विपक्ष सरकार से लड़ रहा था। वे कहते थे टेस्ट मत करो, ट्रीटमेंट मत करवाओ, वैक्सीन मत लगाओ। लेकिन डबल इंजन सरकार ने फ्री टेस्ट, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री वैक्सीन और फ्री राशन देकर जनता की रक्षा की। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने के लिए भी विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, तब भी कांग्रेस और सपा ने दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी, लेकिन इनके घरों में सन्नाटा छाया था। हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इस भव्य आयोजन में हिस्सा लिया, लेकिन विपक्ष तब भी दुष्प्रचार में लगा रहा। जब इनको सत्ता में मौका मिला, तो इन्होंने विकास नहीं किया और आज जब विकास हो रहा है, तो ये बैरियर बनने का काम कर रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन आज यह देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले समय में यह नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कई कदम उठाए।

करणी सेना ने सपा राज्यसभा सांसद के आवास पर हमला बोला, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

आगरा, (हि.स.)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार दोपहर को करणी सेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। कुर्सियां तोड़ डालीं, वहीं पथराव भी किया। पथराव में इंसपेक्टर समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को वहां से हटाया।

सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिए थे। इसको लेकर करणी सेना में काफी नाराजगी थी। इसी के चलते बुधवार दोपहर को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर लेकर आवास पर हमला बोल दिया। कुर्सी तोड़ डाली व जमकर बवाल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया तो उनके साथ भी कार्यकर्ताओं ने हाथापाई कर डाली। पुलिस की बैरीकेडिंग तोड़ दी। पत्थर और कुर्सियां फेंकी, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए, उनमें इंस्पेक्टर हरीपर्वत आलोक कुमार सिंह भी शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके सभी को वहां से हटाया। करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने कहा राज्यसभा सांसद ने क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है। उनको अपने बयान वापस लेकर माफी मांगनी होगी। गौरतलब है कि 21 मार्च को राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने इब्राहीम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। साथ ही उन्हें गद्दार तक कह डाला था।इसी बयान के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना ने सपा सांसद के आवास का घिराव करने का ऐलान किया था।

लोकसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को दी मर्यादित आचरण की नसीहत

नई दिल्ली, (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी को आचरण संबंधी मयार्दाओं के पालन करने की नसीहत दी। शून्यकाल की समाप्ति के पूर्व उन्होंने सदन की नियम प्रक्रिया के तहत मयार्दा और आचरण करने की बात कही।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को मयार्दा और शालीनता के उच्च मानदडों को बनाए रखना चाहिए। सदन में उनके संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं, जब सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप नहीं रहे हैं। इस सदन में पिता-पुत्र मां-बेटी और पति-पत्नी सदस्य रहे हैं। इस संबंध में वे नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि वह लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संख्या नियम 349 में वर्णित नियमों के तहत आचरण करें जो सदन की उच्च मयार्दा के अनुरूप रहना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में नेता विपक्ष पर की टिप्पणी का कोई कारण नहीं बताया। साथ ही राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सदस्य इस पर कुछ बोल पाते इससे पहले अध्यक्ष बिरला अपनी टिप्पणियों के बाद कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर उठकर चले गए।

लोकसभा से बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं पता लोकसभा अध्यक्ष किस विषय पर बात कर रहे थे। अध्यक्ष ने जब टिप्पणी की और उन्होंने बोलना चाहा तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया और वे उठकर चले गए। उन्होंने कहा, जब भी मैं बोलने के लिए उठता हूं, तो वे मुझे नहीं बोलने देते। पिछले 8-10 दिनों में, उन्होंने मुझे कभी बोलने की अनुमति नहीं दी।

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बुधवार को दिल्ली पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि, उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह को सील किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचे। आग लगने वाली जगह को जांच कमेटी के कहने पर सील किया जा रहा है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नई दिल्ली के डीसीपी व अन्य आला अधिकारी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तुगलक रोड के एसएचओ भी मौजूद रहे। आग लगने की सूचना जस्टिस यशवंत वर्मा के निजी सहायक ने 14 मार्च को रात 11.30 बजे दी थी, जिसे आधी रात बुझा लिया गया था।

जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया था। जिसमें जज के सरकारी आवास में नोटों के बंडल जले हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर भी 500 रुपये के जले हुए नोट मिले थे। जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर पर नोटों के बंडल के आरोपों की जांच तीन जजों की इन हाउस कमेटी कर रही है।

पंजाब बजट विफलताओं का खाली डिब्बा : चुग

आलोक पाण्डेय

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुग ने आज पंजाब विधानसभा में पेश भगवंत मान सरकार के बजट को विफल वादों का खाली डिब्बा बताया। चुग ने कहा, दिल्ली की जनता से खारिज होकर भी आम आदमी पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा। 37 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने के वादे का क्या हुआ? किसानों को एमएसपी टॉप-अप का आश्वासन दिया था, वह वादा कहां गया? तीन साल पहले किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, वो भी पूरी तरह से गायब है। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों के साथ जानबूझकर विश्वासघात कर रही है?

चुग ने सवाल उठाया, रेत खनन से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई का दावा किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष केवल 288 करोड़ ही सरकारी खजाने में आए। बाकी पैसा कहां गया? क्या यह पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में चला गया?

शिक्षा क्षेत्र की दुर्दशा पर चुग ने कहा, 1927 में से 855 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों

- **रेत खनन का पैसा आप के फंड में जा रहा है**
- **केजरीवाल-सिसोदिया की छाप वाला बजट, पंजाब में होगा ड्रग स्कैम**
- **रंगला पंजाब' नहीं 'कंगला पंजाब' बना रहे मुख्यमंत्री मान**

में प्रिंसिपल नहीं हैं, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 'स्कूल ऑफ हैप्पीनेस' और 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' की बात करते हैं। क्या पंजाब के बच्चे इन स्कूलों में आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के बारे में पढ़ेंगे या

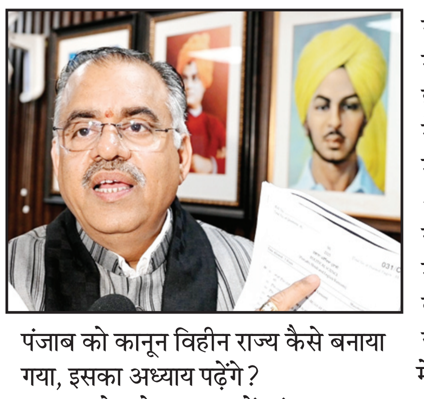

पंजाब को कानून विहीन राज्य कैसे बनाया गया, इसका अध्याय पढ़ेंगे?

चुग ने जोड़ा, हजारों पंजाब राज्य परिवहन कर्मी नियमितीकरण के लिए महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर बजट में उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। लुधियाना और जालंधर के उद्योगपति और व्यापारी 2022 के चुनावी वादों के अनुसार ठोस उद्योग-हितैषी नीतियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बजट में उन्हें भी धोखा मिला।

चुग ने आरोप लगाया, दिल्ली में शराब घोटाला कर चुकी अअढ अब पंजाब में नशा-घोटाले की तैयारी में है। इस बजट पर मनीष सिसोदिया की छाप स्पष्ट नजर आ रही है, जो दिल्ली जैसा शराब घोटाला पंजाब में ड्रग घोटाले के रूप में दोहराने वाले हैं। उन्होंने कहा, नशे के खिलाफ पोस्टर अभियान की आड़ में सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी प्रचार में उड़ाए जाएंगे। चुग ने उद्योगों की अनदेखी पर टिप्पणी करते हुए कहा, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों के उद्यमी 2022 के घोषणापत्र में किए गए उद्योग समर्थक वादों के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बजट में टरटए क्षेत्र की प्रगति और रोजगार सृजन के लिए कोई योजना नहीं है। यह पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। चुग ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त कर्ज लाद दिया गया है। यह साफ दशार्ता है कि 'रंगला पंजाब' का नारा पूरी तरह खोखला है, जिसपर अब 585 करोड़ रुपये और बर्बाद किए जा रहे हैं।

अमेरिका से व्यापार समझौते में देश के हितों का रखा जाएगा ध्यान : जयशंकर

नई दिल्ली, (हि.स.)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की वार्ता के दौरान हमारा पक्ष देश के हितों विशेषकर कृषि से संबंधित मुद्दों पर देश के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों को लेकर हमारी चिंतायें हैं लेकिन समझौता क्या अंतिम रूप लेगा इसे लेकर हमें पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए।

विदेश मंत्री राजधानी में एशिया सोसाइटी पॉलिसी संस्थान की अध्यक्ष डॉ किंग वा सांग की ओर से आयोजित एक संगोष्ठी में बुधवार को यह विचार व्यक्त किए। विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व वातार्कार जेएस दीपक ने इनका ध्यान अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने तथा भारत पर आयात निर्यात के लिए छूट देने पर दवाब बनाने की ओर आकृष्ट किया था।

जयशंकर ने इस बारे में कहा कि हमारे वातार्कार सभी मुद्दों की जानकारी रखते हैं तथा हमें विश्वास है कि वार्ता के दौरान देश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात नई नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले राष्ट्रपति कायार्काल के दौरान बीटीए पर चर्चा शुरू हुई थी लेकिन उस समय इसपर ज्यादा प्रगति नहीं हो पायी थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल में यह चेतावनी दी है कि उनका प्रशासन आगामी दो अप्रैल से अमेरिका में होने वाले आयात पर सीमा शूल्क में बढ़ोत्तरी करेगा। ट्रम्प के अनुसार अमेरिका से आयात पर सीमा शुल्क लगाने वाले देशों पर उतना ही सीमा शुल्क लगाया जाएगा। ट्रम्प प्रशासन की इस घोषणा से भारत सहित कई देशों पर सीमा शूल्क लगने से दवाब पड़ेगा। इससे खाद्यान, डेयरी और मुर्गी पालन क्षेत्र अधिक प्रभावित होंगे। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गत फरवरी में अमेरिका यात्रा के दौरान व्यापार के संबंध में दोनों पक्षों के बीच खुलकर चर्चा हुई थी। इस वर्ष के अंत तक बीटीए को अंजाम देने पर सहमति बनी थी। इसपर इस समय सक्रीय और गहन विचार-विमर्श जारी है। विदेश मंत्री ने चीन के साथ संबंधों के बारे में कहा कि पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों में कुछ सुधार हुआ। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श जारी है। भारत का प्रयास है कि वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुए घटनाक्रम से पहुंचे नुकसान से उबरा जाए तथा संबंधों को पटरी पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अच्छे संबंध दोनों देशों के हित में हैं। वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक हुए घटनाक्रम हमारे संबंधों के लिए अच्छे नहीं थे।

दिल्ली सरकार ने दवा खरीद की नीति में किया बदलाव

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद की नीति में बदलाव किया है। अब सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से ही दवाएं खरीदनी होंगी। स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद केवल इमरजेंसी के समय में ही की जा सकेगी।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 6 मार्च 2025 को दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की गई थी। इस दौरान उन्होंने सभी चिकित्सा अधीक्षकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से दवा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश में भारत सरकार के फार्मास्युटिकल विभाग के तहत एक अधिकृत चैनल पार्टनर के साथ समझौता ज्ञापन करने की जरूरत बताई गई थी, ताकि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सुचारू रूप से दवाओं की खरीद सुनिश्चित की जा सके।

पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि हम दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कदम से मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकेंगी।

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले छह अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही अन्य अस्पतालों में भी नई नीति के तहत जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस नई नीति के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल अपनी दवाओं की आवश्यकताओं की सूची तैयार करें और जन औषधि केंद्रों से सीधे दवा खरीदने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सरकार मरीजों के हितों के साथ के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी और सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों की तरह सुविधा देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

विधायकों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए तदर्थ समिति का गठन

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को विधायकों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने तथा उचित अनुशंसा देने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया। यह निर्णय सदस्यों की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। समिति का उद्देश्य वर्तमान वेतन और भत्तों की स्थिति की जांच करना और उसमें संभावित संशोधनों पर विचार करना है, ताकि विधायकों को उपयुक्त सुविधाएं मिल सकें।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित इस तदर्थ समिति में पांच सदस्य शामिल किए गए हैं। इस समिति के सभापति अभय वर्मा होंगे, जबकि अन्य सदस्यों में सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम शर्मा, संजीव झा और विशेष रवि शामिल हैं।

नई दिल्ली। देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के समर्थन में संविधान सपोर्ट ग्रुप ने आज जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया।

नाबालिग का अपहरण कर हत्या, तीन नाबालिग पकड़े

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तरी जिले के वजीराबाद थाना इलाके स्थित मिलन विहार में एक नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप मृतक के दोस्तों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपित युवकों ने पहले मृतक को कॉल कर मिलने बुलाया फिर उसके पिता को कॉल कर 10 लाख रुपये फिरौती मांगी गई। जिसके बाद 14 साल के नाबालिग का शव खून से लथपथ हालत में मिला।

मृतक की पहचानन वैभव उर्फ कन्नू (15) के रूप में हुई है। डीसीपी राजा बांठिया के अनुसार नाबालिग नौवीं कक्षा का छात्र था। मृतक नाबालिक परिवार के साथ मिलन विहार इलाके में रहता था। उसके पिता कैब चलाते हैं, मृतक परिवार का इकलौता बच्चा था। रविवार को नाबालिग घर पर ही था, जब उसके कुछ दोस्तों का फोन आया और उसे घर के बाहर यमुना पुश्ते पर बुलाया। जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी और पुलिस को भी सूचना दी।

पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस बीच पिता के मोबाइल पर फोन आया और महज कुछ सेकंड की बातचीत में ही मृतक के पिता से अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी और फिरौती की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पिता ने मामले की सूचना पुलिस दी। पुलिस टीम ने तुरंत फोन कॉल को ट्रैक किया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए। जिससे मालूम चला कि नाबालिग अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था। पुलिस को मंगलवार कोशव भलस्वा झील के पास मिला।

डीसीपी के अनुसार उक्त मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़ा है।पूछताछ में पकड़े गए नाबालिगों ने खुलासा किया कि उन्होंने 10 लाख की फिरौती के लिए पीड़ित वैभव का अपहरण कर हत्या करने की योजना बनाई थी। 23 मार्च को वे उसे अपनी बाइक पर घूमने के लिए अपने साथ ले गए। वे उसे भलस्वा झील के पास एक जंगली इलाके में ले गए और उस पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं फेंक कर फरार हो गए।

एनडीएमसी म्यूजिक इन द पार्क शास्त्रीय संगीत को समर्पित तीन संध्याओं का कर रही आयोजन

नई दिल्ली, (हि.स.)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने स्पिक मैके के सहयोग से नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी में शनिवार से सोमवार यानी 29 से 31 मार्च तक शाम 06.30 बजे से रोजाना म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला के तहत शास्त्रीय संगीत समारोह को समर्पित तीन संध्याओं को आयोजित कर रही है। नेहरू पार्क में इस शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए प्रवेश नीति मार्ग की ओर से है और सभी के लिए यह निःशुल्क है।

स्पिक मैके के सहयोग से 21 साल की प्रतिष्ठित संगीत परंपरा के उत्सव को चिह्नित करने के लिए एनडीएमसी शास्त्रीय संगीत को समर्पित तीन संध्याओं प्रस्तुत करके, शास्त्रीय संगीत के छह दिग्गज कलाकारों के साथ 12 अन्य कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी के नेहरू पार्क की पृष्ठभूमि में ये शास्त्रीय संगीत समारोह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और सम्मान प्रस्तुत करेंगे।

एनडीएमसी द्वारा आयोजित होने वाली शास्त्रीय संगीत संध्याओं की शुरूआत डॉ. एल सुब्रमण्यम और अंबी (कर्नाटक वायलिन वादक) द्वारा की जाएगी, जिसमें एन राधाकृष्णन (मृदंगम वादक), अकरम खान (तबला वादक), गणेशन नटराजन (कंजीरा वादक) शामिल होंगे, इसके बाद अश्विनी भिडे देशपांडे (हिंदुस्तानी गायन) के साथ विनोद लेले (तबला), विनय मिश्रा (हारमोनियम) की प्रस्तुति शनिवार 29 मार्च को होगी।

दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत समारोह की सन्ध्याओं के क्रम में सरोद वादक तेजेंद्र नारायण मजूमदार ईशान घोष (तबला वादक) के साथ, संजय सुब्रह्मण्यन (कर्नाटक गायक) के साथ एस वरदराजन (वायलिन वादक), नेवेली बी वेंकटेश (मृदंगम वादक) रविवार 30 मार्च को होगी।

शास्त्रीय संगीत संध्याओं के समापन दिवस अवसर पर उदय बावलकर (हिंदुस्तानी गायक) के साथ सुखद मुंडे (पखावज वादक), प्रसन्ना विश्वनाथन (मुखर सहयोग) और उसके बाद बेगम परवीन सुल्ताना (हिंदुस्तानी संगीत गायिका) के साथ शादाब सुल्ताना (स्वर समर्थन), अकरम खान, (तबला वादक) और विनय मिश्रा (हारमोनियम वादक) अपनी प्रस्तुति से सोमवार 31 मार्च को भी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करेंगे।

उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी द्वारा अपने क्षेत्र में संगीत, नृत्य और प्रदर्शन कला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे उद्देश्य शहरी जीवन को उन्नत करना है।

आज का राशिफल

मेष राशि–स्त्री वर्ग से हर्ष-उल्लास, अधिकारियों का समर्थन फलप्रद होगा, मनोनुकूल कार्य बना लेवें।

वृष राशि–योजनाएं फलीभूत हों, शुभ समाचार संभव बनेंगे, रुके कार्य बन ही जाएंगे।

मिथुन राशि–धन लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष, बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे।

कर्क राशि–कार्य-व्यवस्था की चिन्ता बनी ही रहेगी, प्रयास करने से लाभ होगा।

सिंह राशि–भोग-एश्वर्य की प्राप्ति होगी, कार्यगति उत्तम, सुख के साधन अवश्य बनेंगे।

कन्या राशि–अर्थिक योजना पूर्ण हो, समय पर सोचे कार्य पूर्ण होंगे, रुके कार्य बन ही जायेंगे।

तुला राशि–पारिवारिक बाधायें परेशान करेंगी, विरोधी तत्व कष्टप्रद रखें, ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि–मानसिक बेचैनी, उद्विघ्नता से बचें तथा समय से लाभांवित होंगे।

धनु राशि–कुटुम्ब की समस्याऐं कष्टप्रद हों तथा व्यर्थ भ्रमण में व्यय होगा।

मकर राशि–योजनऐं फलीभूत हो, सफलता के साधन जुटायें तथा कार्य बनें, ध्यान रखें।

कुंभ राशि–स्वभाव में खिन्नता, मानसिक बेचैनी तथा मानसिक कष्ट के साथ शरीर पीड़ा।

मीन राशि–तनाव-क्लेश व अशांति बनेगी, परिश्रम विफल होंगे, कार्यगति मंद हो।

–अम्बुजा तिवारी

सोने की अंगूठी दोषपूर्ण होने की बात कहकर उतरवाई, चार जालसाज पकड़े

नई दिल्ली, (हि.स.)। खुद को हरिद्वार अखाड़े के बड़े साधु और वेदों का अच्छा जानकार बताकर एक युवक से उसकी सोने की अंगूठी में दोष होने की बात कहकर अंगूठी हड़पने वाले नाथ गैंग के चार जालसाजों को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान रिंकू नाथ, साहिल नाथ, रॉकी नाथ और विक्की नाथ के रूप में हुई है। इनके कब्जे से पीड़ित की सोनू की अंगूठी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि बीते रविवार को आईजीआई पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस कॉलर के पास पहुंची। मध्य प्रदेश के रहने वाले गगन जैन ने बताया कि वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह दिल्ली में तीन दिवसीय एआईएमसीएमएम सम्मेलन में भाग लेने आया था। वह होटल लेमन ट्री, एरोसिटी में ठहरा था। करीब साढ़े 11 बजे जब वह होटल से चेकआउट करके गेट नंबर पांच की तरफ से निकला। साधुओं की वेशभूषा में चार लोग उसके पास आए, जिनके शरीर पर राख लगी थी और पैरों में घंटियां बंधी थीं। उन्होंने खुद को हरिद्वार अखाड़े का बड़ा पुजारी और वेदों का जानकार बताया। उन्होंने उसके माथे पर तिलक लगाने की कोशिश की, मना करने पर उसे कहा कि अगर वह गंगा मैया में विश्वास करता है या फिर वह गंगा मैया और महादेव में विश्वास करता है तो तिलक लगवाना होगा। बाद में उनमें से एक ने दो रुपये मांगे। जिस पर उसने उसे 50 रुपये दिए। इसके बाद उन चारों ने उससे कहा कि बच्चा तेरी पहनी अंगूठी खराब है और वह उन्हें दे दे। इसके पहनने से तेरे काम अटक रहे हैं, इसमें दोष है। घबराकर उसने अंगूठी उतारकर दे दी। साधुओं ने कहा कि मुड़कर पीछे देखना नहीं। नहीं तो गलत हो जाएगा तेरे साथ। उसने ऐसा ही किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस टीम ने होटल के बाहर और आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उनके रूट का पता कर चारों को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपितों से पता चला कि चारों रिश्तेदार हैं और सपेरा समुदाय से हैं। हरिद्वार, उप्र में, उन्होंने भक्तों की एक बड़ी भीड़ देखी। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक कई भक्तों ने स्वेच्छा से संतों को पैसे दिए। यह मानते हुए कि इससे उन्हें सौभाग्य मिलेगा। इससे प्रेरित होकर आरोपितों ने पुजारी की पोशाक पहनकर लोगों से की स्थिति का फायदा उठाने की साजिश रची।

आतिशी ने स्पीकर को लिखा पत्र, दो दिन बजट पर चर्चा की मांग की

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आगामी दो दिन तक केवल बजट पर चर्चा कराई जाए। उन्होंने पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण का मुद्दा भी उठाया है।

आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बजट पेश किया। वार्षिक बजट अनुमान किसी भी विधानसभा के समक्ष रखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के लक्ष्मीबाई कॉलेज ने बुधवार को अपना 59वां वार्षिक दिवस मनाया तथा अहिल्याबाई मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

सूडोकु नवताल- 7382

✶✲✲✲✲ सरल

			2				3	
		9		8		2	6	4
1				3	6		9	
4		3						
	8			2			1	
						8		6
	4		7	5				3
3	7	5		4		1		
	2				8			

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7381 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

दैनिक पंचांग

27 मार्च 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

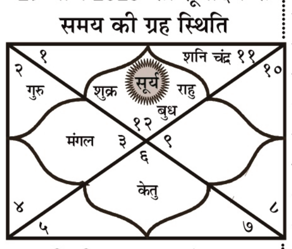

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मीन में	मेष	06.54 बजे से
चंद्र	कुंभ में	वृष	08.35 बजे से
मंगल	मिथुन में	मिथुन	10.33 बजे से
बुध	मीन में	कर्क	12.46 बजे से
गुरु	वृष में	सिंह	15.02 बजे से
शुक्र	मीन में	कन्या	17.14 बजे से
शनि	कुंभ में	तुला	19.25 बजे से
राहु	मीन में	वृश्चिक	21.40 ब.से
केतु	कन्या में	धनु	23.56 बजे से
राहुकाल		मकर	02.01 बजे से
1.30 से 3.00		कुंभ	03.47 बजे से
बजे तक		मीन	05.20 बजे से

गुरुवार 2025 वर्ष का 86 वा दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** बसंत। **विक्रम संवत्** 2081 **शक संवत्** 1946 **मास** चैत्र (दक्षिण भारत में फाल्गुन) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** त्रयोदशी 23.04 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** शतभिषा 00.34 बजे रात्र को समाप्त। **योग** साध्य 09.25 बजे को समाप्त। **करण** गर 12.28 बजे तदनन्तर वणिज 23.04 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.0 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 02° 36' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872296 **जूलियन दिन** 2460761.5 **कलियुग संवत्** 5125 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2551 **हिजरी सन्** 1446 **महीना** रमजान **तारीख** 26 **विशेष** प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
शुभ	05.54 से	07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से	07.11 बजे तक
रोग	07.22 से	08.51 बजे तक	चर	07.11 से	08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से	10.19 बजे तक	रोग	08.43 से	10.15 बजे तक
चर	10.19 से	11.47 बजे तक	काल	10.15 से	11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से	01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से	01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से	02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से	02.51 बजे तक
काल	02.43 से	04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से	04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से	05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ– **शुभत्व श्रेष्ठ** शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8444

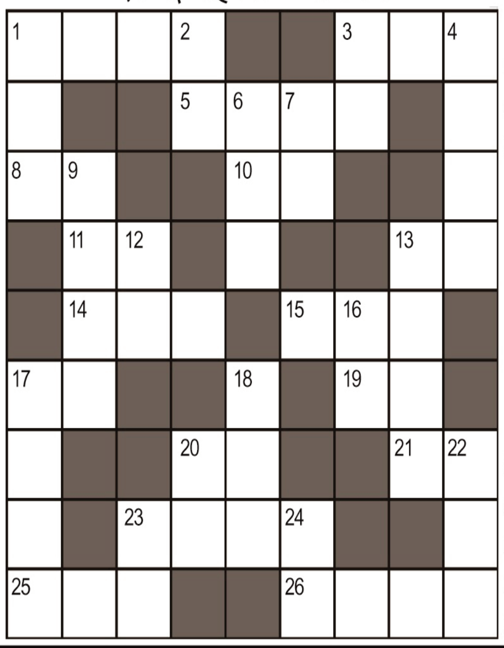

बाएँ से दाएँ

1. साले की पत्नी-4
3. उच्च कुल का -3
5. पाताल-4
8. व्यंग, चुटीली बात-2
10. दुख, कष्ट-2
11. शराब का प्याला-2
13. सत्य, तेज-2
14. जुड़वा-3
15. विश्राम, राहत-3
17. मक्का-मदीना की यात्रा-2
19. झुका हुआ-2
20. टैक्स, हाथ-2
21. होठ, अधर-2
23. सुरक्षित-4
25. नाश, विनाश, विध्वंस-3
26. निश्चित -4

ऊपर से नीचे

1. नदी-3
2. संपत्ति, धन-2
3. वंश, खानदान-2
4. उत्तमता, परिष्कृतता-4
6. समुद्र, दरिया-3
7. अंधकार-2
9. जो जायज न हो-4
12. संस्कृत में 'मेरा'-2
13. सपाट- 4
16. जांघ-2
17. पैगंबर, महापुरुष-4
18. रनिवास (उर्दू-3)
20. हुनर, फन-2
22. देह, काया-3
23. गलत का विलोम -2
24. निश्चित-2

शब्द पहेली - 8443 का हल

फि	त	र	त		स	ला	म	त
रं		त	ल	ब	गा	र		मी
गी	ला			द			ह	ज
	ल		क	न	क		म	
ध	कि	या	ना		या	या	व	र
	ता		त	म	स		त	
ऐ	ब			ना			न	न
न		ख	ल	ना	य	क		क
क	र	त	ब		म	ल	म	ल

Jagrutidaur.com, Bangalore

आखिरकार अमेरिकी कंपनी से एलसीए मार्क-1ए के लिए शुरू हुई इंजन की आपूर्ति

नई दिल्ली, (हि.स.)। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट एलसीए मार्क-1ए के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इंजन की आपूर्ति शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल ही वाशिंगटन यात्रा के दौरान इंजन आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया गया था। भारतीय वायु सेना के साथ फरवरी, 2021 में अनुबंध होने के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसी साल मार्च से नए विमान की आपूर्ति होनी थी, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन की अमेरिका से आपूर्ति में देरी की वजह से इंतजार लंबा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान तेजस एमके-1ए में लगने वाले जनरल इलेक्ट्रिक एफ-404 इंजन की आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया था। अब जीई एयरोस्पेस ने एचएएल को 99 एफ-404 इंजनों में से पहले की डिलीवरी करने का ऐलान 25 मार्च को कर दिया है। अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने एक बयान में कहा है कि एफ-404 इंजनों की आपूर्ति अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास करके भारत की सेना के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जीई एयरोस्पेस का कहना है कि भारत में सैन्य जेट प्रणोदन सहयोग का एक मजबूत इतिहास है। एचएएल के साथ 40 साल के संबंधों और देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ाते हुए 1980 के दशक में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ सहयोग करने के बाद जीई एयरोस्पेस के एफ-404 इंजन को 2004 में सिंगल-इंजन तेजस के लिए चुना गया था। यह इंजन भारत के एकल इंजन वाले लड़ाकू विमान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। जीई एयरोस्पेस और तेजस की टीमों ने इसे भारतीय वायु सेना की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए कई वर्षों तक मिलकर काम किया। एफ-404 के साथ 2008 में अपने पहले परीक्षण उड़ान में विमान कई मिशन ऊंचाइयों पर चढ़ा और मैक 1.1 की गति हासिल की। 2016 तक जीई एयरोस्पेस ने एचएएल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी की और एलसीए तेजस के लिए 65 इंजन वितरित किए। जीई एयरोस्पेस के बयान में बताया गया कि एचएएल ने 2021 में तेजस मार्क-1ए के लिए अतिरिक्त 99 इंजनों का ऑर्डर दिया, तो हमारी टीम ने पांच वर्षों से निष्क्रिय इंजन उत्पादन लाइन को फिर से शुरू किया।

जेट इंजन उत्पादन लाइन को फिर से शुरू करना चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कंपनी का कहना है कि इस सप्ताह पहले इंजन की डिलीवरी इस बात का प्रमाण है कि हमने पिछले 40 वर्षों में एचएएल के साथ मिलकर क्या हासिल किया है तथा यह भारत की सेना के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने की हमारी संयुक्त क्षमता का प्रतीक है।

पटना। बिहार पुलिस बहाली में लड़कियों को लम्बाई और उम्र में छूट की मांग के लिए प्रदर्शन करते अभ्यर्थी।

संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और स्वास्थ्य जेपी नड्डा ने लिवर स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया।

अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। इसमें अमित शाह पर राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाने का आरोप है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिए गए अपने नोटिस में जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया है। जयराम रमेश ने 25 मार्च, 2025 को आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान अमित शाह के जवाब का हवाला दिया है।

जयराम रमेश ने दावा किया कि उस दिन अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में पीएम राहत कोष बनाया गया था और एनडीए यानी मोदी के शासनकाल में पीएम केयर्स फंड बना। कांग्रेस के शासनकाल में केवल एक परिवार का नियंत्रण होता था और कांग्रेस अध्यक्ष इसके सदस्य थे। कांग्रेस अध्यक्ष सरकारी कोष का हिस्सा हैं, वे इस देश के लोगों को क्या जवाब देंगे। क्या कोई इसे पढ़ता या देखता नहीं है?

कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसा कि उपरोक्त के अवलोकन से देखा जा सकता है कि गृहमंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख किया था और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (एनपीएमआरएफ) के कामकाज के संबंध में उनकी मंशा पर संदेह जताया था। उन्होंने तर्क दिया कि सदन के किसी भी सदस्य पर टिप्पणी करना या अपमानजनक बातें कहना विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा सदन की अवमानना है।

जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले में गृहमंत्री ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए पूर्व नियोजित उद्देश्य से उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। गृहमंत्री का बयान सरासर झूठा और मानहानिकारक है। यह सोनिया गांधी के विशेषाधिकार का हनन है। इसलिए यह विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना का भी मामला बनता है। इसलिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 188 के तहत सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाने के लिए दिया गया। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

गरीब कैदियों के लिए केंद्र की वित्तीय सहायता योजना को बहुत कम लोग अपना रहे

नई दिल्ली, (हि.स.)। देश की तमाम जेलों में बंद गरीब कैदियों को जुमार्ना राशि और जमानत के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये आवंटित करती है। हालांकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में योजना के शुरू होने से लेकर आज तक 12 राज्यों ने केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते से महज 22,84,451 रुपये की धनराशि ही निकाली है।

गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में गरीब कैदियों की सहायता के लिए योजना शुरू की थी।

योजना के कार्यान्वयन के लिए 19 जून 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया को साझा किया गया था।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 20-20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इसका उद्देश्य उन गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है, जो जुमार्ना न चुका पाने या जमानत पर रिहाई के लिए बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि उपलब्ध कराई गई और उन्हें सीएनए खाते से धनराशि निकालने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि आज तक 12 राज्यों ने सीएनए खाते से 22,84,451 रुपये की धनराशि निकाली है।

ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों को सौ करोड़ की संपत्ति की जब्त

भोपाल, (हि.स.)। लोकायुक्त की छापे में करोड़ों की संपत्ति का आसामी निकले मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल से पूछताछ के बाद 100.36 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी माना है कि भोपाल के मेंडोरी के जंगल में लावारिस इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये की नकदी सौरभ की ही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को जारी सूचना में कहा है कि पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा द्वारा अपने और रिश्तेदारों, सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटाई है। इसकी पड़ताल के बाद ईडी ने इन सबके स्वामित्व वाली, कंट्रोल वाली फर्म, कंपनियां, सोसायटी के नाम पर अर्जित 92.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी ने इसे आपराधिक आय (पीओसी) दशार्ते हुए यह कार्रवाई की है। इन संपत्तियों को उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार इन सहयोगियों, संस्थाओं में शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर, मेसर्स अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अविरल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यू आर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। ईडी ने रिपोर्ट में कहा है कि आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर की इनोवा गाड़ी से नकदी और सोना जब्त किया था। ईडी की जांच में पता चला है कि इनोवा कार से जब्त नकदी और सोना सौरभ शर्मा का ही था।

ईडी ने लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(बी) के तहत सौरभ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में पता चला कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहयोगियों और कंपनियों, फर्मों, सोसाइटी के नाम पर भी अलग-अलग चल और अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इसमें अवैध तरीके से आपराधिक गतिविधि के माध्यम से मिली ब्लैक मनी को व्हाइट करके कई अज्ञात व्यक्तियों से अनसेफ लोन की व्यवस्था की गई थी।

इससे पहले सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में (जेल में बंद) हैं। ईडी ने कहा है कि पहले भी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी जिसके कारण 8.29 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था और 2.50 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी। साथ ही 14.20 लाख रुपए और 9.17 लाख रुपये की चांदी जब्त की गई है। अब तक ईडी द्वारा इस मामले में कुल 100.36 करोड़ रुपये की कुर्की और जब्ती की गई है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसी दौरान भोपाल के मेंडोरी में इनोवा कार से 11 करोड़ रुपये कैश और 52 किलो गोल्ड जब्त किए गए थे। इसका लिंक भी सौरभ से जुड़ा था। इसके बाद सौरभ और उसके सहयोगियों की बेशुमार संपत्ति सामने आई थी। हालांकि, अब तक हुई पूछताछ में सौरभ शर्मा ने यह स्वीकार नहीं किया है कि मेंडोरी में इनोवा कार में मिला सोना और कैश उसका है।

इधर, एक अन्य कार्यवाही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय प्रशासन विकास विभाग इंदौर एवं उज्जैन पूर्व उप निदेशक अशोक शर्मा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही की है। शर्मा के विरुद्ध की गई जांच के 95 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें 1 अप्रेल 1998 से 17 जनवरी 2010 तक की जांच अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक 1.64 करोड़ रुपए की संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था।

नक्सली संगठन नाबालिगों को दे रहे गुरिल्ला वार व बम बनाने की ट्रेनिंग

जगदलपुर, (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली संगठन नाबालिग बच्चे-बच्चियों के हाथों में हथियार पकड़ा रहे हैं। साथ ही जंगल में इनको बम बनाना सिखाने व गुरिल्ला वार की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका खुलासा दंतेवाड़ा-बीजापुर जिले की सीमा पर मंगलवार को हुए मुठभेड़ में मारे गये 25 लाख रुपये के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर के पास से बरामद चार पन्नों के पत्र से हुआ है। पत्र में मिले सबूत के अनुसार जंगल में नाबालिक बच्चों को हथियार चलाना (स्नाइपर चलाना) और आईईडी बनाना भी सिखा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सली लीडर सुधाकर उर्फ मुरली के पास से पुलिस ने सामान के साथ तेलुगु भाषा में लिखा एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें नक्सल संगठन में नए लड़कों की भर्ती और नक्सली लीडर्स के साथ बैठक सहित कई बातें लिखी हुई हैं। पत्र में लिखा है कि कुछ दिन पहले नक्सलियों की उत्तर बस्तर ब्यूरो में माड़ इलाके में सीसीएम, डीकेएसजेडसी कैडर के नक्सलियों की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में नक्सल संगठन के काम, नुकसान, कामयाबी और चुनौतियों की समीक्षा की गई, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका उल्लेख पत्र में किया गया है।

पत्र में लिखा है कि जिन लड़कों की भर्ती की गई है, वे अभी लड़ने योग्य नहीं हैं। नक्सल संगठन को लड़ाके चाहिए, जो भर्ती हुए हैं, उन्हें नक्सल नीति, राजनीति, लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। उनको अभी लड़ने योग्य बनाने में समय लगेगा। जो संगठन में हैं, उनमें ज्यादातर लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ मारे गए हैं। अगर नक्सल संगठन में नई भर्तियां नहीं होती हैं तो नक्सलवाद का अस्तित्व खतरे में है। पत्र को अलग-अलग एरिया कमेटी में भेजकर उन्हें नई भर्ती और मीटिंग में हुई समीक्षा की जानकारी दी गई है।

नक्सलियों के चार पन्नों के तेलुगु भाषा में हाथ से लिखे पत्र में पूरा लेखा-जोखा है। लिखा है कि माड़ डिवीजन के इंद्रावती एरिया कमेटी और नेलनार एरिया में 130 लोगों की नई भर्ती हुई है, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दिए हैं। 18 से 22 उम्र के युवक-युवतियों को हथियार थमाया गया है, लेकिन 9 से 17 उम्र तक के अभी बच्चे हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेपक टाकरा विश्वकप 2025 में भारतीय सेपक टाकरा दल को उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए पहला स्वर्ण पदक लाने पर टीम की सराहना की।

राज्य सभा में सोनिया गांधी ने मातृ वंदन योजना को लेकर सरकार को घेरा

नई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान गरीब गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले मातृ वंदन योजना के तहत निर्धारित राशि नहीं मुहैया कराने का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपये प्रति बच्चा पोषण के लिए देने का भी प्रावधान है।

सोनिया गांधी ने कहा कि योजना 2017 में शुरू हुई थी, जो इस प्रावधान को ही पूरा करने के लिए थी लेकिन इस योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर केवल पांच हजार रुपये ही दिए जा रहे हैं। दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो यही लाभ दिया जा रहा है। साल 2022-23 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 68 फीसदी महिलाओं को इस योजना के तहत केवल एक किश्त ही दी गई। इसके अगले ही साल इसमें भारी गिरावट आई और आंकड़ा 12 फीसदी पर आ गया। सोनिया गांधी ने कहा कि एनएफएसए के तहत पूर्ण प्रसव के दौरान दिए जाने वाले इस लाभ के लिए 12000 करोड़ रुपये वार्षिक बजट की जरूरत है। यह आश्चर्यजनक है कि बजट में एनएफएसए के तहत मातृ वंदन योजना के लिए आवंटन का आंकड़ा ही नहीं दिया गया है।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने मिड डे मील में उपयोग किए जाने वाले तेल की मात्रा को 10 प्रतिशत तक कम करने का मुद्दा उठाया। डोला सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों में मोटापे को देखते हुए स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में तेल की खपत में 10 प्रतिशत कम करने की नीति तैयार की जा रही है। बिना किसी अध्ययन के इस तरह की नीति सही नहीं है। स्कूलों में दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। उस पर उनके खाने में 10 प्रतिशत तक वसा को कम करने की नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में वसा (फैट) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना किसी रिसर्च और अध्ययन के इस तरह स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन में फैट की मात्रा को 10 प्रतिशत तक की कमी करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश से भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने गाजीपुर में सेना की कैंटीन शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 30026 सेवानिवृत्त सैनिक, 300 से ज्यादा वीर नारियों और 40 हजार से ज्यादा कार्यरत सैनिक हैं लेकिन वहां सीएसडी कैंटीन नहीं है। कैंटीन के नाम पर यहां वाराणसी का एक्सटेंशन काउंटर है। सैनिकों को कैंटीन से सामान लेने और ईसीएचएस की सुविधा के लिए वाराणसी जाना पड़ता है, जो सौ किलोमीटर से अधिक दूर है। गाजीपुर में में ईसीएचएस और सीएसडी कैंटीन की सुविधा शुरू की जानी चाहिए।

डीएमके के सांसद पी विल्सन ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के हेरफेरयुक्त वाली रोस्टर प्रणाली का मुद्दा उठाया, जिसके तहत हाशिए पर पड़े समुदायों को संगठनों के प्रमुखों और विभागों के सचिवों जैसे मुख्यधारा के पदों पर प्रवेश करने से रोकना है। शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए पी विल्सन ने कहा कि आरक्षण को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय के साधन के रूप में पेश किया गया था और आरक्षण रोस्टर इस नीति को लागू करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 जुलाई 1997 में उल्लिखित आरक्षण रोस्टर मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है।

दिव्य भारत
नई दिल्ली, गुरुवार
27 मार्च, 2025

सम्पादकीय

दिल्लीवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा की सरकार ने विधानसभा में एक लख करोड़ रुपये का बजट पेश कर दिया है। प्रथम दृष्टि में देखने से ही लगता है कि यह बजट दिल्ली को विकास की राह पर लेजाना है। पिछले वर्ष आम आदमी पार्टी की सरकार से लगभग 32 प्रतिशत अधिक का यह बजट यह आशा दिलाता है कि चुनाव अभियान के दौरान प्रधान में भी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिल्ली के बहुमुखी विकास को बढ़ाने देने वाले वायदों को शीघ्र ही पूरा किया जा सकेगा बजट में भाजपा के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र की झलक दिखती है, तो दिल्ली को डबल इंजन की सरकार होने का भी लाभ मिलता नजर भारत है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण ही दिल्ली सरकार केन्द्र की मदद वाली कई बड़ी योजनाओं को बजट में शामिल कर पायी है।

बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। साथ ही जटिल समस्याओं से जूझ रही जनता को राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। बजट में दिल्ली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने के साथ-साथ, व्यापारियों, महिलाओं गरीबों, छात्रों, युकओं से लेकर झुग्गी झोपड़ियों, में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद नजर आती है। वित्तमंत्री का भी कार्यभार संभाल रही मुख्यमंली रेखा गुप्ता ने सबसे लम्बे 138 मिनट के बजट भाषण में अपने पहले बजट को ऐतिहासिक करार दिया। मुख्य मंत्री ने कहा कि बजटीय प्राविधान में 31.5%. की वृद्धि देश भर में तुलनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि है।

दिल्ली सरकार के नये बजट में कहा गया है कि वह राजधानी में नई औद्योगिक नीति लायेगी, जिससे दिल्ल में व्यापार करने में आसानी होगी। एकल खिड़की प्रणाली के जरिये व्यापार को आसान बनाया जायेगा, इसके लिए नई औद्योगिक नीति और कई गोदाम नीति लाई जायेगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जायेगी। इसके अलावा दिल्ली में पहली बार वैश्विक निवेश शिएखर सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

बजट में यमुना नदी की सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। यह योजना साबरमती रिवर फ्रंट योजना से विशेष रूप से प्रेरित है। सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया है, जिससे यह तय होगा कि 40 सीवरेज प्लांट के विकेन्द्रीकर के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही यमुना में जाये। इसके भलावा एसटीपी की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रु० और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रूपयों का प्राविधान किया गया है। बजट में स्वच्छ पेयजल के लिए 9000 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र के लिए 12592 करोड़ रुपये, आवाजाही सुगम बनाने के लिए जैसे एक्सप्रेस वे, एलीवेटेड वे, सड़कों में सुधार आदि के लिए 3843 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। अब दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत के लिए दस लाख रुपए का कवर मिलेगा। केन्द्र के पांच लाख रुपए के कवर के साथ दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा मिलेगा। इसके लिए 2144 करोड रुपये का प्राविधान है। कुलमिलाकर सरकार का बजट दिल्ली वालों के चेहरे पर नई मुस्कान लाने वाला है।

डी. के. शिवकुमार का संकेत संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है

चन्दन कुमार

मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलनेह्व संबंधी कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित टिप्पणी पर संसद के दोनों सदनों मे जमकर हंगामा हुआ। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों को आरक्षण की सुविधा देने के लिए संविधान में बदलाव करने का सुझाव दिया था। यह मुद्दा लोकसभा में गूंजा और सत्तारूढ़ भाजपा ने इस विचार पर सवाल उठाया और शिवकुमार को हटाने की मांग की।

कर्नाटक विधानसभा में ठेकेदारों को ठेके देने के लिए 4% आरक्षण (अल्पसंख्यकों को) देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसको लेकर कर्नाटका विधानसभा मे मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कोर्ट का रुख किया हुआ है। भाजपा का कहना है कि सरदार पटेल और बी. आर. अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। संविधान में संशोधन किया गया और आर्थिक मानदंड को आधार बनाया गया, जिसे बाद में अदालतों ने बरकरार रखा। संविधान में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक सकारात्मक तंत्र प्रदान किया गया है। हलांकि, सबसे पहले तेलंगाना विधानसभा में कॉंग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। अब कर्नाटका मे डी. के. शिवकुमार ने फिर कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है और संविधान बदलने का काम भी कांग्रेस ही करेगी।

दरअसल, डीके शिवकुमार एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जहां उनसे सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने और भाजपा द्वारा इसे अदालत में चुनौती देने की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया। उसका जवाब देते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि देखते हैं कि क्या होता है। हमने जो शुरू किया है, मुझे पता है कि इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे। इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव करने हैं...संविधान भी बदल रहा है ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। मामले को तूल पकड़ता देख उपमुख्यमंत्री ने धर्म आधारित आरक्षण को समायोजित करने के लिए संविधान में बदलाव के संकेत से इनकार किया। अब ऐसे मे आज के डिजिटल युग मे जहां सभी चीजे रेकॉर्डे है। कोई अपनी बातों से कैसे मुकर सकता है? जो कॉंग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान के नाम पर लड़ी हो, जिन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगया हो कि भाजपा सत्ता मे आई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। आज वही कॉंग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कर रही है! क्या इससे एससी,एसटी, ओबीसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है?

आरएनआई नं. DELHIN/2009/28518 स्वामी, सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक रमाकांत पाण्डेय द्वारा दिव्य भारत प्रकाशन के लिए न-93 डी नारायण नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफल इंफोटेक लि., प्रेस, सी-9 सेक्टर 3 नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : रमाकांत पाण्डेय, कार्यकारी सम्पादक : आलोक पाण्डेय, फोन : 7701825882, 7905152597, पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी।
E-mail : newdibyabharat@gmail.com

असंख्य हिन्दू मंदिरों को तोड़ने के 'इतिहास' का नाम है 'औरंगजेब'

अरुण कुमार दीक्षित

औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। औरंगजेब ने इस्लाम को राज्य धर्म बनाया। बहुसंख्यक हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। उसने सामाजिक, राजनीतिक दुर्व्यवहार किया। वह कभी भी सर्व समाज का हितैषी नहीं रहा। सम्पूर्ण मानवता के लिए कभी स्वीकार करने वाला शासक नहीं बन पाया। साम्राज्य जरूर बढ़ता गया। उसने हिन्दुओं के प्रति ही नहीं शिया मुसलमानों के प्रति भी घृणित आचरण किया। राज्य की सेवाओं में शियाओं को औरंगजेब ने पृथक कर रखा था। औरंगजेब की क्रूरता की पराकाष्ठा इस सीमा तक थी, कि उसने हिन्दुओं पर (जजिया) तीर्थ कर व्यापारिक कर जैसी कठोरताएं की थी। हिन्दुओं को भारत में ही अपमानित करने के साथ उसने राज्य की सेवाओं से हटाने की भी कार्रवाई की थी। असंख्य हिन्दू मंदिरों को तोड़ने, देवी-देवताओं की मूर्तियों को अपमानित कर तोड़ने के इतिहास का नाम है औरंगजेब।

औरंगजेब ने कभी मानवीय मूल्यों को नहीं समझा। वह भारत को दारुल हरब में परिवर्तित करने के लिए जीवन भर जुटा रहा। प्रत्येक भारतवासी को यह बात समझना होगा कि वह विदेशी हमलावर था। वह लाखों कत्ल करने वाले तैमूरलंग, बाबर, नादिरशाह, गजनी, गोरी, गाजी, खिलजी की तरह लुटेरा युद्ध पिपासु था। इन विदेशी आक्रांताओं ने लगातार मंदिरों, नगरों, गांवों को लूटा। कत्लेआम किया। भारत की संस्कृति, सभ्यता को तहस-नहस करने में कोताही नहीं बरती। बावजूद इसके भारत मे इनकी तरफदारी करने वाले अनेक लोग सक्रिय हैं। औरंगजेब को लेकर पूरे राष्ट्र में बहस है। एक तरफ बहस में भारत को एक संस्कृति एक राष्ट्र मानने जानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणकारियों को उनके सैकड़ों वर्ष मृत्यु के पश्चात गले लगाने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रतीकों को लेकर हल्ला मचा रहे हैं।

ऐसी स्थितियां भारत के मन को चिंतित और व्यथित करने वाली हैं। इससे अनेक प्रश्न भी उभर रहे हैं। भारत के वह लोग जो विदेशी हमलावरों की स्मृतियों को आखिर क्यों सजाने और संवारने को लेकर तत्पर हैं। झगड़े पर आमादा हैं। यह प्रश्न राजनीतिक नहीं है। यह भारत के स्व और भारत की संस्कृति पर हमला है। भारत की रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि से जुड़े प्रश्न हैं। इस पर तो बात होनी ही चाहिए कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मण्डन करने वाले आखिर चाहते क्या है? औरंगजेब के कालखंड में हिन्दू अपने मंदिरों की मरम्मत नहीं कर सकते थे। उसका सीधा आदेश था कि मंदिरों की मरम्मत न करने दी जाए। उसने अपने सूबेदारों को सभी हिन्दू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा भी दी थी। इससे हिन्दू अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार न कर पाएं। बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किए गए। साथ ही अधिकांश उत्तर भारत के बड़े-बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया था। औरंगजेब के अधीनस्थ हिन्दू राजाओं के राज्यों में भी मंदिर, पाठशालाएं ध्वस्त की गईं। इन सभी स्थानों पर औरंगजेब के आदेश अनुसार मस्जिद बनाई गईं। 1679 में हिंदुओं पर जजिया (धार्मिक कर) लगा दिया गया।

इसके लिए सभी गैर मुसलमानों को तीन वर्गों में बांटा गया। हिन्दुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। जबकि मुसलमान तो व्यापारिक कर से भी मुक्त थे। हिन्दू व्यापारियों से वस्तुओं के मूल्य का पांच फीसदी धन कर के रूप में लिया जा रहा था। हिन्दुओं को लगान और विशेष स्थान की नियुक्तियों से हटा दिया गया था। साल 1674 में गुजरात में धार्मिक अनुदान में हिन्दुओं को दी गई भूमि को जब्त कर लिया गया। 1688 में हिन्दुओं के त्योहार और उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसी समय राजपूतों के अतिरिक्त सभी हिन्दुओं को पालकी या अच्छे घोड़े की सवारी करने और हथियार रखने से भी रोक दिया गया था। इस तरह की प्रताड़ना का सीधा अर्थ धर्म परिवर्तन ही था। इतिहासकार लेनपूल ने लिखा है, "अपने इतिहास में मुगलों ने पहली बार एक कट्टर मुसलमान को बादशाह के रूप में देखा। औरंगजेब 40 वर्ष की आयु में बादशाह बना था।" उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कार्यों पर विचार करते हुए डॉ. एसआर शर्मा ने लिखा, "ये सभी कार्य एक योग्य शासक अथवा एक निर्माणकर्ता राजनीतिज्ञ के नहीं थे, बल्कि एक अंधी धर्मांधता का विस्फोट था जो, उन्हें निःसंदेह अन्य सभी क्षेत्रों में मेधावी औरंगजेब के लिए शोभनीय न था।"

औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह जाटों ने किया था। मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर मस्जिद स्थापित की। औरंगजेब वास्तव में राजपूतों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। शिवाजी भारत के राष्ट्रनायक थे। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ई. में हुआ। 1660 में शिवाजी का बीजापुर और दक्षिण के सूबेदारों संघर्ष हुआ। राजा जयसिंह के समझाने पर शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा आए। वहां औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर दिया। शिवाजी वहां से अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। तीन वर्ष संघर्ष रुका रहा। 16 जून 1674 ई. को रायगढ़ में बनारस के वैदिक अध्येता पं. विश्वेश्वर गागभट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया। छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण कर उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। 14 अप्रैल 1680 ई. में शिवाजी की मृत्यु हो गई। औरंगजेब कभी भी शिवाजी से युद्ध में सफलता नहीं पा सका (पृष्ठ संख्या 131,158 मध्यकालीन इतिहास एलपी शर्मा)। मराठों का औरंगजेब से संघर्ष आजीवन चला। औरंगजेब कभी सफल नहीं हुआ। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसे दौलताबाद से चार मील दूर शेख जैन उल हक के मजार के निकट दफन किया गया।

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति अपने धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, साहित्य और कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारत की संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है, उसकी मुख्य विशेषता अध्यात्म की भावना है। भारत का इतिहास प्राचीन है। यहां की सभ्यता संसार की प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। वेद दुनिया का प्राचीनतम अभिलेख है। प्राचीन संसार की अनेक सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है। वेद, उपनिषद , गीता ज्ञान की धारा आज भी प्रवाहमान है। भारत की संस्कृति में राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर की सर्व भूत हिते रतः की धारा है। भारत ने अपने गौरवशाली इतिहास को लगातार विकसित किया है। वही इतिहास भारतीय संस्कृति है। एक तरफ भारत की सहिष्णु संस्कृति है। दूसरी ओर हिंसक रक्तपात करने वालों का कलुषित इतिहास है। वह भारत की संस्कृति सभ्यता पर सांस्कृतिक प्रतिमानों पर सदियों से हमलावर रहने वाले है। विध्वंसक हैं। पूर्व में एक शासन पूरे भारत में न रहना अलग बात है। मगर भारतीय अनुभूति यही रही है कि राष्ट्र धार्मिक,साहित्यिक, सांस्कृतिक रूप से एक है। यह कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में अभिव्यक्त होना चाहिए। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मुस्लिम धमार्चार्यों के अनुसार दो प्रकार के देश होते थे। जिन देशों के निवासी मुसलमान हों, उन्हें वे दारुल इस्लाम शांति मय देश कहते थे। और जहां इस्लाम का प्रचार न हो उन्हें वे दारुल हरब युद्धस्थली समझते थे। मुस्लिम धमार्चार्यों का मत था, कि दारुल हरब के खिलाफ जिहाद करना और उनको जीतकर इस्लाम के झंडे के नीचे ले आना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश अरब साम्राज्य के संगठित होने पर 712 ईस्वी में एक अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। जीतकर अपने कब्जे में लिया था। तब से अब तक हमले जारी हैं। आज भारत पूरी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया के देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह राष्ट्र के ममत्व एकत्व के जागरण में रहे। विभिन्न सम्प्रदायों, पंथिक आस्थाओं का लक्ष्य राष्ट्र सर्वोपरि ही होना है। यहीं से वसुधैव कुटुम्बकम का राजमार्ग जाता है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

रसूल के सम्मान की दुहाई देनेवाले ओवैसी और उनकी निर्लज्जता

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुसलमानों के हिमायती ओवैसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने आरोप मात्र के आधार पर बुलडोजर चला दिया, जो असंवैधानिक है। अगर कार्रवाई करनी थी तो अदालत में सबूत पेश कर सजा दिलवाते, उनके घरवालों का क्या दोष इनका कहना है कि हमारे रसूलल्लाह के खिलाफ अनाप-शनाप बकने की जुर्रत करने वाले एक बाबा के घर पर बुलडोजर नहीं चलता, क्योंकि वो संस्कारी है, हालाँकि उसने जो कहा वो जुर्म था।

क्या वास्तव में बात इतनी सीधी है, जो यहां असदुद्दीन ओवैसी समझा रहे हैं! आपके रसूलल्लाह की शान, शान है, उसकी वंदगी में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए गुस्ताखी माफ नहीं होगी, लेकिन इस्लाम के नाम पर आपके लोग जो करें सब जायज है? फहीम खान का वे कोई दोष नहीं मानते? यानी पुलिस झूठ बोल रही है? कैमरे झूठ बोल रहे हैं? जिन लोगों ने पुलिस के सामने गवाही दी है, वे सभी झूठ बोल रहे हैं? यह सच किसी से छिपा नहीं रह गया है कि फहीम खान नागपुर में दंगे के लिए भीड़ इकट्ठा करने और भड़काऊ भाषण देकर पथराव-हिंसा करवाने का आरोपित है, इनके हिसाब से ये सच नहीं है। वह तो नेकनीयत वाला व्यक्ति है, उसे बेकार में पुलिस फंसा रही है? औवेसी के हिसाब से यहां कोई सच बोल रहा है तो वे स्वयं ही हैं!

फहीम खान जैसे लोग इस्लाम के नाम पर लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें भड़काएं, जिहादी नारे लगाए और सुनियोजित तरीके से हमला करें और करवाएं फिर भी सरकार, पुलिस इसलिए कोई कार्रवाई न करें, क्यों कि वह अल्पसंख्यक उसमें भी खासकर मुसलमान है? नागपुर में सोमवार 17 मार्च 2025 को क्या हो रहा था? मुस्लिम भीड़ ने खोज-खोजकर हिंदू घरों और गाड़ियों को निशाना बनाया, इसके अधिक इस मुस्लिम भीड़ ने तुलसी के पौधे को तोड़ने के साथ चुन-चुन कर गाड़ियों में रखी भगवान की मूर्तियों, स्वास्तिक और मूर्तियाँ देखकर उन्हें जलाया, जबकि मुस्लिम घरों और गाड़ियों को छुआ तक नहीं। नकाबपोश हमलावर पेट्रोल बम, पत्थर और हथियारों से लैस थे। ये हिन्दू घरों और बच्चों तक पर पत्थर फेंक रहे थे। यानी असदुद्दीन ओवैसी को संविधान की जब याद नहीं आती? जब उनके तथाकथित भाईजान-चाचाजान ये सभी हिन्दुओं पर हिंसा कर रहे थे, उनके देवताओं को आग के हवाले कर रहे थे।

किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनके साथ घटनाएं घटीं, उनके कई वीडियो आज सोशल मीडिया में मौजूद हैं, क्या इन नफरती भाईजान को इन सभी का दर्द दिखाई नहीं देता, इन वक्त के मारे, हम दर्दों के लिए औवेसी को संविधान की याद नहीं आती? आज हमारे सामने अनेकों चश्मदीद गवाह है, जो इस हिंसा का शिकार हुए हैं, क्या वे सब भी झूठे हैं? औरंगजेब विवाद में नागपुर में हुई हिंसा के दौरान मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदू युवक वरुण की दुकान को आग के हवाले कर दिया था। पीड़ित दुकानदार ने कहा, भाईचारे से रह रहे थे तो दुकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? इतने लोगों ने गाड़ी क्यों जला दी? यहाँ पर एक भी दुकान का कांच नहीं टूटा है। हम हिंदू हैं इसलिए हमें निशाना बनाते हुए हमारी दुकानों पर हमला हुआ। आज दुकान तोड़ी है, कल घर में घुस जाएंगे। क्या यहां वरुण झूठ बोल रहा है?

नागपुर हिंसा में घायल डीसीपी निकेतन कदम ने बताया, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उनके पास हथियार, पेट्रोल और डंडे थे। इसके बाद पत्थरबाजी हुई और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम भीड़ से एक व्यक्ति आगे आया और मुझ पर हमला किया, जिससे मेरे हाथ में गहरी चोट लग गई। एक पीड़ित महिला ने बताया, दंगाइयों के हाथ में तलवारें थीं। मुस्लिम भीड़ ने घरों के दरवाजों पर तलवार से हमला भी किया। उनके घर में एक महिला का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, फिर भी दंगाइयों ने उस घर पर ईंट-पत्थर फेंककर कांच तोड़ दिए। नीचे खड़ी 8 से 10 कारों में आग लगा दी गई।

हसनपुर इलाके में दुकान चला रहे हिंदू दुकानदार ने हिंसा की आपबीती सुनाते हुए बताया, मेरी किराना स्टोर की दुकान है। मैं दुकान बंद करके खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी पथराव शुरू हो गया। भीड़ ने मेरी दुकान के सामने खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जब मैंने आग बुझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंककर मुझे घायल कर दिया। नागपुर के दंगे में सुनील पेशने नाम के हिंदू युवक के कार को मुस्लिम भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। घटना की व्यथा बताते हुए सुनील ने कहा, घटना करीब रात 8:30 बजे हुई। 500 से 1000 लोगों की भीड़ ने पत्थरबाजी की। उन्होंने हमारी कार को भी जला दिया... करीब 25-30 वाहनों में तोड़फोड़ की गई।

मुस्लिम भीड़ ने फायरकर्मी कपिल बर्वे को घायल कर अधमरा कर दिया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया, मुस्लिम भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी की और उन पर चाकू व तलवारों से हमला किया, ताकि हम आगजनी को कंट्रोल न कर पाएं। नागपुर हिंसा में मुस्लिम भीड़ ने बंडु क्लिनिक चला रहे एक हिंदू डॉक्टर ए. आर. श्रीवास के घर में घुसकर दवा और क्लिनिक में तोड़कर सामान फेंक दी। घर में घुसकर भगवान के कमरे में पत्थरबाजी की और लाइट कनेक्शन काट दिए। वहीं, औरंगजेब को लेकर हुई हिंसा में पीड़ित एक हिंदू युवक ने कहा, मुस्लिम भीड़ पहले जुटी और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिये और फिर मेरे घर के सामने रखी रामनवमी की झांकियों को आग लगा दिया। भीड़ ने मेरे बाईक पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। यहां इस तरह के अनेकों लोग हैं, जिनके सामने ये पूरी घटना घटी।

वास्तव में विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल सही कहते हैं कि आज मुसलमानों के तथाकथित हिमायती ओवैसी जैसों से पूछा जाना चाहिए कि जो वे पैगम्बर, रसूलल्लाह का हवाला दे रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, उनका यह संविधान तब कहां चला जाता है, जब ये मुसलमानों द्वारा की जा रही हिंसा पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं? ये मुसलमान जब हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र नष्ट कर रहे थे, उन्हें आग के हवाले कर रहे थे, तब तो फिर पूरे हिन्दू समाज को गुस्सा आ जाना चाहिए? दूसरा आपको किसी संत-महात्मा द्वारा इस्लाम को लेकर कही गई बात तो ध्यान हैं, लेकिन जो आपके लोग सिर्फ कह नहीं रहे, वह तो करके दिखाते हैं। उनके लिए आप चुप हो जाते हैं। वास्तव में ओवैसी जी ये दोहरा चरित्र यहां चलनेवाला नहीं है। देश की जनता आपके कृत्यों को देख रही है ओवैसी साहब, कुछ तो अपने रसूल से डरो, सच कहने का साहस दिखाओ।

जलवायु परिवर्तन पर देश में नई नीति की जरूरत

राकेश दुबे

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च बुलेटिन में प्रकाशित अध्ययन में एक गंभीर चिंता जताई गई है, जो देश में वर्षा के वितरण में तेजी से आ रहे बदलाव और खाद्यान्न फसलों पर इसके असर से जुड़ी है। अध्ययन कहता है कि भारतीय कृषि अब भी काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु परिवर्तन से बेअसर रहने वाले नई किस्मों के बीज तैयार होने से राहत तो मिली है मगर मॉनसूनी बारिश अब भी निर्णायक होती है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा खरीफ सत्र में कृषि उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।

वर्षा का तरीका बदलने या सूखे जैसी स्थिति से फसल उगाने का चक्र बिगड़ जाता है और कीटों एवं पौधों से जुड़ी बीमारियों की समस्या भी बढ़ जाती है। पर्याप्त और समान वर्षा होने से कृषि उत्पादकता बढ़ जाती है। मॉनसून में अच्छी बारिश रबी सत्र के अनुकूल होती है। मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने और जलाशयों में पानी का स्तर अधिक रहने से गेहूं, सरसों और दलहन जैसी फसलों की बुआई के लिए आदर्श स्थिति तैयार होती है।

खरीफ सत्र में मोटे अनाज, तिलहन, दलहन और चावल की उपज में सालाना वृद्धि के आंकड़े देखें तो जिस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सभी फसलों के लिए बेहतर रहा उस साल उत्पादन भी ज्यादा रहा लेकिन अतिवृष्टि ने मक्के और तिलहन की उपज बिगाड़ी। अध्ययन में कहा गया है कि उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मॉनसूनी बारिश कब आती है। उदाहरण के लिए जून और जुलाई में कम बारिश मक्का, दलहन और सोयाबीन के लिए खासतौर पर नुकसानदेह होती है क्योंकि मिट्टी में नमी कम होने के कारण बुआई अटक जाती है और पौधों की शुरूआती बढ़वार पर भी असर पड़ता है।

इसी तरह कटाई के समय अत्यधिक वर्षा से तिलहन उत्पादन घट जाता है। पिछले साल मॉनसून में शानदार वर्षा और सटीक ठंड रहने से चालू वित्त वर्ष में फसलों का उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले खरीफ का उत्पादन 7.9 प्रतिशत और रबी का 6 प्रतिशत बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 2025 के लिए मॉनसून के अनुमान जारी नहीं किए हैं मगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अनुमान है कि भारत में इस साल वर्षा सामान्य या इससे अधिक हो सकती है।

ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में आने वाले बदलाव कृषि उत्पादन पर ज्यादा असर डाल सकते हैं। मौसम की अतिरंजना अब अनोखी बात नहीं रह गई है। भारत में पिछले साल 365 में से 322 दिन मौसम की अति दिखी थी। इससे देश में 4.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें प्रभावित हुईं। 2023 में 318 दिन मौसम ऐसा रहा था। जब तक इन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बहु-आयामी नीति नहीं अपनाई जाती है तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती ही रहेंगी।

पिछले साल कम और असमान वर्षा के कारण गर्म हवा और बाढ़ की 250 घटनाएं सामने आईं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान और बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन घटने और इनमें पोषक तत्व कम होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यों की तरफ कदम बढ़ाना आवश्यक हो गया है। कृषि में जलवायु परिवर्तन सहने की क्षमता रखने तौर-तरीके, नालियों की प्रणाली में सुधार, बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन और तकनीक अपनाकर कृषि क्षेत्र में क्षमता एवं टिकाऊपन बढ़ाया जा सकता है।

लंबे अरसे के लिए जल प्रबंधन पर भी हमें सतर्क रहना होगा। जैविक या रसायन रहित कृषि के बजाय प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना होगा। इससे अलग-अलग मियाद वाली विविध फसलों से किसानों की आय ही नहीं बढ़ती बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर भारत को जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने और अनुकूल रणनीति अपनाने के लिए काम करना होगा।

कालीमठ मंदिर में अस्त्र-शस्त्र धारण कर विराजमान मां सरस्वती

शक्तिपीठ कालीमठ में मां सरस्वती अस्त्र-शस्त्र धारण कर विराजमान हैं। यह देशभर में संभवतः एकमात्र मंदिर है, जहां मां सरस्वती इस रूप में हैं। साथ ही इस शक्तिपीठ में त्रिशक्ति (मां महाकाली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती) अपने-अपने मंदिर विराजमान हैं। वैष्णो देवी मंदिर में यह तीन देवियां पिंडी रूप में हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र के साथ ही वर्षभर लाखों श्रद्धालु आराध्य के दर्शन कर पूजा-पाठ के लिए पहुंचते हैं।

रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुप्तकाशी-कालीमठ-कोटमा-चौमासी मोटर मार्ग पर गुप्तकाशी से लगभग 10 किमी की दूरी पर कालीमठ मंदिर स्थित है। यहां काली नदी किनारे मां महाकाली का शक्तिपीठ है। इस मंदिर परिसर में मां महाकाली की प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना होती है।

यहां मां काली की मूर्ति नहीं है, बल्कि श्रीयंत्र की पूजा की जाती है, जो रजतपट से ढका रहता है। इस मंदिर परिसर में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के प्राचीन मंदिर है, जहां आराध्य की काले पत्थर की मूर्तियां हैं। विशेष यह है कि, यहां मां सरस्वती की मूर्ति अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो अन्य जगहों से अलग है। क्योंकि, अन्य जहां भी मंदिरों में मां सरस्वती की मूर्ति है, वह वीणा धारण किए हुए है। आचार्य दिनेश गौड़ बताते हैं कि, मां सरस्वती विद्या की देवी हैं।

कालीमठ में मां सरस्वती अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए विराजमान हैं। उन्होंने बताया कि देशभर में शक्तिपीठ कालीमठ एकमात्र मंदिर है, जहां त्रिशक्ति एक ही परिसर में अपने-अपने मंदिर में विराजमान हैं। यहां वर्षभर देवी भक्तों की भीड़ जुटी रहती है। स्थानीय सहित जिले और बाहरी से देवी भक्त चैत्र व शारदीय नवरात्र के साथ ही अन्य मौकों पर यहां पहुंचते हैं और आराध्य देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर के प्रबंधक प्रकाश पुरोहित बताते हैं कि कालीमठ पहुंचकर श्रद्धालु मां देवी मां के तीन रूपों के एकसाथ दर्शन होते हैं, जो दुर्लभ है।

जम्मू कश्मीर के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाना मेरा संकल्प है : एलजी सिन्हा

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज आईआईएम जम्मू में एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने पर नीति आयोग की कार्यशाला में भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में, उपराज्यपाल ने नीति आयोग, आईआईएम जम्मू और अन्य हितधारकों को कार्यशाला के लिए नीति निमार्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और विचारकों को एक साथ लाने के लिए बधाई दी, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों- कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन में चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना था। उपराज्यपाल ने कहा, विकास के माहौल को बनाने के लिए सुधारों पर इस तरह के विचार-विमर्श से भारत के केंद्र शासित प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जोर दिया कि एमएसएमई क्षेत्र के सभी हितधारकों के बीच संचार गहरा होना चाहिए, सुधार निर्बाध होने चाहिए और नीति निमार्ताओं और उद्यमियों को भागीदार के रूप में काम करना चाहिए। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। उपराज्यपाल ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारा उद्योग आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी डर या आशंका के आगे बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हमें अपने प्रदर्शन में सुधार करने और पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और नए पर्यटन स्थलों के विकास में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक योजना के तहत प्रोत्साहनों ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उपराज्यपाल ने आगे कहा कि शांति और अनुकूल स्थिति ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष निवेश भी सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, यह जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया है और बेहतर बाजार संपर्क के माध्यम से, उत्पादों को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में हमारे एमएसएमई नई चुनौतियों का सामना करेंगे और नए अवसरों से लाभान्वित होंगे। उपराज्यपाल ने पर्यटन की पेशकश में विविधता लाने और जम्मू कश्मीर में बेहतर पर्यटक-केंद्रित सुविधाओं के विकास में निजी खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा शांति विकास, संपन्न व्यवसाय और समृद्ध पर्यटन क्षेत्र के लिए एक शर्त है। हम शांति हितधारकों में भी वृद्धि देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की बदली हुई तस्वीर को दशार्ता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर का भविष्य भी भारत के साथ है। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती।

उपराज्यपाल ने कैलाख संदेश पंचांग का विमोचन किया।

उपायुक्त श्रीनगर ने एसपी कॉलेज में रोजगार मेले का उद्घाटन किया

दिव्य भारत संवाददाता

श्रीनगर। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) श्रीनगर, डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट ने आज श्री प्रताप कॉलेज, श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन किया। जिला प्रशासन श्रीनगर द्वारा जिला रोजगार और परामर्श केंद्र (डीईसीसी) श्रीनगर के सहयोग से आयोजित जॉब फेयर का उद्देश्य नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच की खाई को पाटना था।

इस अवसर पर बोलते हुए, डीसी ने रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने और जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की करियर आकांक्षाओं का समर्थन करने में इस तरह की पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी भाग लेने वाली कंपनियों का आभार भी व्यक्त किया। इस आयोजन में बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, बैंकिंग और इलेक्ट्रिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 20 कंपनियां शामिल हुईं। इन कंपनियों ने अपने रिक्त पदों को प्रदर्शित किया और बेरोजगार युवाओं से सीधे तौर पर जुड़कर उन्हें उपलब्ध नौकरी के अवसरों, आवश्यक कौशल और आवश्यक मानव संसाधनों के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान की।

नौकरी मेले के दौरान कई युवा नौकरी चाहने वालों को साक्षात्कार के दूसरे दौर के लिए चुना गया, जो रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस कार्यक्रम में आसपास के कॉलेजों के छात्रों और उत्तीर्ण स्नातकों की उत्साही भागीदारी देखी गई,

- **रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने और बेरोजगार युवाओं की करियर आकांक्षाओं का समर्थन करने में इस तरह की पहल के महत्व पर प्रकाश डाला**

जिसने युवाओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने में इसके प्रभाव को उजागर किया। जिला प्रशासन और डीईसीसी श्रीनगर इस तरह की पहल के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखता है।

राजौरी में जालसाजी के मामलों में शामिल आधार ऑपरेटरों को डीसी ने तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया

दिव्य भारत संवाददाता

राजौरी। आधार नामांकन में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने राजौरी में जालसाजी के मामलों में शामिल पाए गए आधार ऑपरेटरों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है, विशेष रूप से आधार अपडेट और निर्माण के समय जन्म तिथि (डीओबी) में हेरफेर।

उपायुक्त की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के दौरान, यह पता चला कि कुछ ऑपरेटरों ने स्थापित दिशानिर्देशों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिससे आधार नामांकन प्रक्रिया की अखंडता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा हुई हैं।

उपायुक्त के निर्देश पर, डीएसईओ संदीप शर्मा ने आधार ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबित आधार ऑपरेटरों में अवैस अहमद, हक दरहाल थानामंडी, मोहम्मद अल्ताफ, सरकारी जीएचएसएस चिंगस, अमृत अंजुम, आईसीडीएस दरहाल मुख्यालय थानामंडी आईसीडीएस सीडीपीओ कार्यालय, करण कुमार, सीडीपीओ कार्यालय कालाकोट, अब्दुल रजाक, सीडीपीओ कार्यालय कालाकोट, वजार हुसैन, प्रिया गोल्डस्मिथ टेराथ के पास शामिल थे।

संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन ऑपरेटरों की सभी आधार-संबंधी गतिविधियों को तुरंत बंद करें और उनके आधार किट जब्त करें। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही सुनिश्चित करने और भविष्य में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए स्थापित मानदंडों के अनुसार कानूनी और विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी। मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ ही संबंधित तहसीलदार को दो दिनों के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णायक कार्रवाई आधार प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और नामांकन प्रक्रिया में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

उपराज्यपाल ने कैलाख संदेश पंचांग का विमोचन किया

जम्मू। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 'कैलाख संदेश पंचांग कैलेंडर' के 7वें संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर राजभवन में न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल और डॉ. गोविंद शर्मा और डॉ. मीना शर्मा सहित श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित थे।

उपराज्यपाल से पहलगाम विधायक ने मुलाकात की

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। पहलगाम से विधान सभा सदस्य श्री अल्ताफ अहमद वानी ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू संचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों से उपराज्यपाल को अवगत कराया।

उपायुक्त ने गांव सनाई-पुंछ में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।

उपायुक्त ने गांव सनाई-पुंछ में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। उपायुक्त विकास कुंडल ने आज सुरनकोट के उपमंडल के गांव सनाई का दौरा किया और सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम की प्रगति का निरीक्षण किया। स्थानीय एसडीएम फारूक खान, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, मनोज गुप्ता, संबंधित एईई, जेई और अन्य अधिकारियों के साथ, उपायुक्त ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास का निरीक्षण किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने यूटी कैपेक्स के तहत शाह करीम जियारत पर बेला सनाई मोहल्ला द्रोगियां में निमार्णाधीन बेली टाइप 22-मीटर स्पैन मोटरेबल पुल की प्रगति का आकलन किया, जो मोहल्ला डोगरियां को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने 152 मीटर लंबे मोटरेबल पुल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें एक अतिरिक्त स्पैन और मुख्य सड़क से सनाई में जियारत सईद करीम शाह तक पहुंच मार्ग शामिल है, जिसे नाबार्ड आरआईडीएफ योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है।

यह पुल कल्लर कट्टल, नडयाली, मरहोटे और पामरोटे को जोड़ने के लिए आवश्यक है। उपायुक्त ने संबंधित निष्पादन एजेंसियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर पहुंच और सुविधा मिल सके। इसके अलावा, उपायुक्त ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और रमजान के पवित्र महीने के दौरान राशन वितरण और अन्य सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी ली।

उपायुक्त बारामूला ने आकांक्षी ब्लॉक सिंहपोरा में मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की

दिव्य भारत संवाददाता

बारामूला। लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में, आज आकांक्षी ब्लॉक सिंहपोरा पट्टन के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुंड ख्वाजा कासिम में भस्मक और वेंडिंग मशीनों के उपयोग पर वितरण सह अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बारामूला के उपायुक्त (डीसी) मिंगा शेरपा ने संयुक्त निदेशक योजना, जावेद अहमद, एसडीएम पट्टन और वात्सल्य फाउंडेशन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न स्कूलों के 50 स्कूल प्रमुखों के बीच छात्राओं की सुविधा के लिए भस्मक वितरित किए।

इससे पहले, डीसी ने वात्सल्य फाउंडेशन वडोदरा द्वारा दान की गई नेहलपोरा पट्टन में सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, डीसी ने युवा लड़कियों की भलाई के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व पर

- **नेहलपोरा में सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया**
- **स्कूल प्रमुखों के बीच भस्मक और वेंडिंग मशीनें वितरित कीं**

प्रकाश डाला और सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए इस स्वचालित इकाई की स्थापना की दिशा में इस सहयोगी पहल के लिए वात्सल्य फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। डीसी ने आगे कहा कि छात्राओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ये सैनिटरी नैपकिन सभी सरकारी संस्थानों को आपूर्ति की जाएंगी।

इस बीच, डीसी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी नामित संस्थानों में वेंडिंग मशीनों और भस्मक के उचित उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान, डीसी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ भी बातचीत की और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

कठुआ में संकल्प योजना का लाभ उठाकर 25 को मिली नियुक्ति

दिव्य भारत संवाददाता

कठुआ। कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर डॉ. राकेश मिन्हास ने बुधवार को संकल्प योजना के 25 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम स्थानीय कार्यबल को उद्योग-संबंधित कौशल और नौकरी के अवसरों से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लाभार्थियों ने चिनाब टेक्सटाइल मिल्स में ऑटोकॉनर टेंटर और रिंग फ्रेम डॉफर में विशेष प्रशिक्षण लिया, जिससे उन्हें उद्योग-संबंधित विशेषज्ञता से लैस किया गया। कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से संकल्प योजना, कठुआ के बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तियों को सार्थक रोजगार हासिल करने में मदद करने के लिए संरचित प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है।

कार्यक्रम में बोलते हुए, डॉ. राकेश मिन्हास ने कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, युवाओं से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेने का आग्रह किया। उन्होंने कठुआ के विस्तारित उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के प्रचुर अवसरों पर प्रकाश डाला और इच्छुक पेशेवरों को स्थायी करियर विकास के लिए बाजार की जरूरतों के साथ अपने कौशल को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में एडीसी रंजीत सिंह, सीपीओ रंजीत ठाकुर, अधीक्षक आईटीआई कठुआ, इंजीनियर अजय कुमार, प्रशिक्षण प्रमुख सीटीएम संदीप कुमार शामिल हुए। उनकी उपस्थिति ने एक कुशल और रोजगार योग्य कार्यबल बनाने के लिए प्रशासन, उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित किया। यह पहल जिला प्रशासन द्वारा प्रतिभाओं को पोषित करने, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए तैयार एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्यबल सुनिश्चित करके कठुआ की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के चल रहे प्रयासों को दशार्ती है।

ब्रिगेडियर डीएन पांडे ने भद्रवाह का दो दिवसीय दौरा संपन्न किया

दिव्य भारत संवाददाता

भद्रवाह। ग्रुप कमांडर जम्मू ब्रिगेडियर डीएन पांडे ने 10 जेके एनसीसी बटालियन भद्रवाह का अपना दो दिवसीय दौरा संपन्न किया। उन्होंने एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों के साथ गहन चर्चा की। ब्रिगेडियर पांडे ने नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा के महत्व पर जोर दिया और कैडेटों को सामाजिक विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

अपने दौरे के हिस्से के रूप में, ब्रिगेडियर पांडे ने भद्रवाह और डोडा में सरकारी डिग्री कॉलेजों (जीडीसी) का दौरा किया, जहां उन्होंने संस्थानों के प्रिंसिपल डॉ. अत्तर सिंह कोतवाल और डॉ. जावेद इकबाल जरगर के साथ बातचीत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के भारत के सपने को साकार करने में योगदान देने का आग्रह किया। ग्रुप कमांडर ने रोटरी क्लब जेएंडके द्वारा चिनाब घाटी में आयोजित किए जा रहे आगामी मेगा मेडिकल कैंप पर चर्चा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह से भी मुलाकात की।

उपायुक्त बारामूला ने आकांक्षी ब्लॉक सिंहपोरा में मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के कारण विपक्षी दलों ने किया संसद अवरुद्ध

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल सरकार द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के कारण विपक्षी दलों ने बुधवार को दिनभर संसद को अवरुद्ध रखा है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तरफ से स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए सदन की कारवाई नहीं चलने दी।

प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग को पदमुक्त करने के निर्णय के विरोध में विपक्षी दलों ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। प्रमुख विपक्षी दल माओवादी सहित एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय जनमोर्चा और नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने सामूहिक रूप से सदन को अवरुद्ध किया है।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ने सदन में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग की बर्खास्तगी पर प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देने की मांग की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अपने स्थान पर ही खड़े होकर स्पीकर से सदन की कार्रवाई नहीं चलाने और प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री ओली स्वयं सदन में आकर जवाब नहीं देते तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं चलने दी जाएगी।

विपक्षी दलों के द्वारा सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई अवरुद्ध करने के कारण स्पीकर देवराज घिमिरे ने पहले सदन की कार्रवाई को 10 मिनट और फिर बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्षी दल के प्रमुख सचेतकों की बैठक बुलाई लेकिन सत्तापक्ष के तरफ से एमाले पार्टी के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने कहा कि विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की बर्खास्तगी पर प्रधानमंत्री को सदन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दलों को जवाब ही चाहिए तो ऊर्जा मंत्री आकर सदन में जवाब दे सकते हैं। लेकिन सत्तापक्ष के जवाब से विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देने की बात पर अडिग रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन की कार्रवाई को चलाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाने के बाद स्पीकर घिमिरे ने वृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित होने की सूचना प्रकाशित कर दी। विपक्षी दलों ने कल भी प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा दोनों सदनों की कार्रवाई को नहीं चलने देने की बात दोहराई है।

चिली में पुलिस अधिकारी बचाव वाली शील्ड लेकर हिंसा को रोकने का प्रयास करते हुए। यहां इंड्रस्टीयल फिशिंग का कोटा बढ़ाये जाने के बाद हिंसा शुरू हो गयी।

बैंकाक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोनगटन शिनवात्रा अविश्वास प्रस्ताव के पहले संसद में पहुंचीं।

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हमास को कड़ा संदेश, बंधकों की रिहाई न होने पर बढ़ाएंगे दबाव

यरुशलम, (हि.स.)। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर हमास गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं करता है, तो इजराइल उस पर दबाव बढ़ाने के लिए और कड़े कदम उठाएगा। बुधवार को संसद (नेसेट) को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, जितना अधिक हमास बंधकों को रिहा करने से इनकार करेगा, उतना ही अधिक हम उस पर दबाव बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल इसके लिए क्षेत्रीय कब्जे समेत अन्य रणनीतिक उपाय करेगा, हालांकि उन्होंने इन कदमों का पूरा विवरण नहीं दिया। नेतन्याहू की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गाजा में संघर्ष जारी है और युद्धविराम की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। इजराइल का दावा है कि हमास के पास अब भी कई बंधक हैं, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में हुए हमले के बाद पकड़ लिया गया था।

इजराइल ने पहले भी हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा में सैन्य अभियान तेज किए हैं और हाल ही में कई इलाकों में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने दोनों पक्षों से संघर्ष विराम और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इस बीच, गाजा में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जहां नागरिकों को मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

हमास की इजराइल को धमकी, गाजा में हमले नहीं रोके तो बंधकों को मार दिया जाएगा

दोहा/गाजा पट्टी, (हि.स.)। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले जारी रहे तो वह बंधकों की हत्या कर देगा। इजराइल का बलपूर्वक बंधकों को छुड़ाने का सपना पूरा नहीं होगा। 'अरब न्यूज' के अनुसार, समूह ने आज दोहा में जारी बयान में कहा कि वह बंधकों को मारना नहीं चाहता। वह उन्हें जीवित रखने के हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इजराइल के गाजा में बरसते बम उनके जीवन को पल-पल खतरे में डाल रहे हैं।

हमास ने कहा कि इजराइल ने कई बार बंधकों को बलपूर्वक वापस लेने का प्रयास किया है। हर बार उसे अपने लोगों को ताबूतों में ले जाना पड़ा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के पिछले सप्ताह शुरू हुए हमले में अब तक कम से कम 830 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के ताजा हमलों के बाद संघर्ष विराम टूट चुका है।

अल जजीरा न्यूज चैनल के अनुसार, पिछले 24 घंटों में गाजा पर इजराइली हमलों में कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और मलबे से एक शव बरामद किया गया है। इजराइल के सुरक्षा बल (आईडीएफ) सीरिया पर भी बम बरसा रहे हैं। इस बमबारी में डेरा में कम से कम छह लोग मारे गए हैं। कतर और सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। उधर, अमेरिका की सेना यमन पर बम बरसा रही है। इजराइल ने सात अक्टूबर, 2023 को किए गए हमलों के बाद गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर कम से कम 1,139 लोगों को मौत के घाट उतारकर 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया था।

सीएनएन न्यूज चैनल के अनुसार, उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों ने हमास के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वह नारे लगा रहे हैं, हमास आतंकवादी है। भगवान के लिए उन्हें हमास की कैद से मुक्त कराओ। सोशल मीडिया पर साझा एक संदेश में बुधवार को गाजा में नौ हमास विरोधी प्रदर्शनों का आह्वान किया गया। उल्लेखनीय है कि 2006 के चुनाव और फतह के साथ संक्षिप्त गृह युद्ध के बाद गाजा पर 2007 से हमास का नियंत्रण है। सत्रह महीने के युद्ध ने गाजा के अधिकांश हिस्से को मलबे के ढेर में बदल दिया है। एनबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, यह गाजा के लोग पहली बार हमास के खिलाफ लामबंद हुए हैं। मंगलवार को बेत लाहिया शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

व्हाइट हाउस को झटका, काला सागर समझौते को लागू करने पर क्रेमलिन की शर्त

वाशिंगटन/मॉस्को/कीव, (हि.स.)। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को पूरे भरोसे के साथ कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों ने काला सागर में बल प्रयोग बंद करने पर सहमति जताई है। यह एक सैद्धांतिक समझौता है। इस पर क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस को झटका देते हुए कठोरता के साथ कहा कि इसे लागू करने से पहले उसकी कई शर्तें हैं। समझौता तभी लागू होगा, जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेलेंस्की ने मास्को पर नई शर्तें जोड़कर मध्यस्थों को धोखा देने का आरोप लगाया है। सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रात्रिकालीन संबोधन में कहा, "वे (रूस) पहले से ही समझौतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में हमारे मध्यस्थों और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं।" हाल के दिनों में सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई अलग-अलग बैठकें कीं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को दो बयान जारी किए। दोनों में रूस और यूक्रेन के साथ हुए समझौते की रूपरेखा का उल्लेख किया। इन बयानों में कहा गया, " अमेरिका और संबंधित देशों में से प्रत्येक ने सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के उपयोग को रोकने पर सहमति व्यक्त की है।"

व्हाइट हाउस के बयान के तत्काल बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि यूक्रेन काला सागर में सैन्य बल का प्रयोग बंद करने पर सहमत हो गया है। इसी दौरान क्रेमलिन के बयान में कहा गया कि वह इस समझौते को तभी लागू करेगा जब उसके बैंकों और खाद्य और उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बिना उकसावे के आक्रमण शुरू करने के बाद रूस पर यह प्रतिबंध लगाए गए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उनका प्रशासन रूस की शर्तों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, पांच या छह शर्तें हैं। हम उन सभी पर विचार कर रहे हैं।" दिन में विचार रखने के बाद जेलेंस्की ने रात्रिकालीन संबोधन में मॉस्को को खरी खोटी सुनाई। तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस चाहता है कि यह समझौता निष्पक्ष हो। यह याद रखना है कि पिछली बार हमने काला सागर समझौते को वास्तव में लागू करने का प्रयास किया था। मगर दूसरे पक्ष ने इसे नहीं माना। इसलिए इस बार फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जाएगा।

समझा जा रहा है कि काला सागर में तनाव को कम करने के अपने प्रयासों के तहत ट्रंप ने कीव और मास्को दोनों खुश किया है। इसमें एक प्रमुख वादा शामिल है- "यह समझौता कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए विश्व बाजार में रूस की पहुंच को बहाल करने, समुद्री बीमा लागत को कम करने और ऐसे लेनदेन के लिए बंदरगाहों और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।" सनद रहे कीव और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने पहले ही युद्धविराम लागू होने से पहले प्रतिबंधों को हटाने के खिलाफ चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस के बयानों में यह भी कहा गया कि अमेरिका और दोनों देश रूस और यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौते को "कार्यान्वित करने के लिए उपाय विकसित करने" पर सहमत हुए हैं। जेलेंस्की और क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस के इस बयान की पुष्टि की है। क्रेमलिन ने कहा कि ऊर्जा केंद्रों पर यह रोक 18 मार्च से शुरू हुई और 30 दिनों के लिए प्रभावी होगी, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। बाद में जेलेंस्की ने मॉस्को के इस दावे को खारिज कर दिया कि दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर रोक लग गई है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन झूठ बोल रहा है। यूक्रेन के साथ वार्ता के परिणामों को रेखांकित करने वाले बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका युद्ध कैदियों के आदान-प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और जबरन स्थानांतरित यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। रूसी और अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को रियाद के रिट्ज-कार्लटन होटल में मुलाकात की थी। इसी स्थान पर एक दिन पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की थी।

रमजान में पाकिस्तान पर खुदा मेहरबान, खूब धन की वर्षा हो रही

इस्लामाबाद। ऐसा लगता है कि रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान पर खुदा मेहरबान हो गया है। पड़ोसी देश तेजी से परेशानी के दिनों से बाहर आ रहा है। उसकी आर्थिक सेहत पटरी पर आने लगी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ महीनों में मुल्क के खजाने में धन की वर्षा हो रही है। दरअसल,पाई-पाई को मोहताज हो चुकी पाकिस्तानी सरकार को पिछले दिनों वहां की अदालतों से बड़ी राहत मिली। एक अदालती फैसले से एक झटके में करीब 35 अरब रुपये मिल गए।

वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के साथ एक नए 1.3 अरब डॉलर (36.43 हजार करोड़ रुपये) के कर्ज कार्यक्रम पर सहमति बनाई है। साथ ही, मौजूदा राहत पैकेज की समीक्षा भी की गई है, इसके तहत अगर मंजूरी मिलती है, तब पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर (लगभग 28 हजार करोड़ रुपये) और मिल सकते है। यह नया कर्ज 28 महीने का होगा और इसका मकसद पाकिस्तान को पर्यावरण चेंज से निपटने और उसकी चुनौतियों को कम करने में मदद करना है। आईएमएफ ने कहा कि इस नए कार्यक्रम और मौजूदा कर्ज की समीक्षा को अभी फंड के कार्यकारी बोर्ड से मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि, बोर्ड की मंजूरी आमतौर पर औपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसके बाद फंड जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान 2023 में कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया था। इससे देश का कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। तब आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर का राहत पैकेज देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था। इसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। वहीं महंगाई दर कम हुई है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है। आईएमएफ के मिशन प्रमुख ने कहा कि पिछले 18 महीनों में, पाकिस्तान ने मुश्किल वैश्विक माहौल के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और भरोसा बहाल करने में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान देश ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी हालात बेहतर करने की कोशिश की। यह नया कर्ज खास तौर पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए है। पाकिस्तान में हाल के सालों में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा।

नेपाल में राजशाही की वापसी की फिराक में ज्ञानेन्द्र शाह, काठमांडू में 28 मार्च को शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का मिला साथ

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के राजशाही के वापसी के लिए किए जा रहे प्रयासों के समर्थन में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने एक माह के देशव्यापी आंदोलन के अपने कार्यक्रम की घोषणा की है।

पार्टी इस अवधि में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध सभा, धरना और प्रदर्शन करेगी। पार्टी 28 मार्च को काठमांडू में पूर्व राजा के समर्थन में होने वाले शक्ति (जन) प्रदर्शन में जोर-शोर से हिस्सा लेगी

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की दो दिनों तक चली आंदोलन समिति की बैठक के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। आंदोलन परिचालन समिति के संयोजक बनाए गए सासंद धवल शमशेर राणा ने आज सुबह संवाददाता सम्मेलन में रूपरेखा को सार्वजनिक किया है। राणा के मुताबिक सबसे पहले 28 मार्च को काठमांडू में होने वाले जन प्रदर्शन में शाह के समर्थन में सड़कों पर उतरा जाएगा।

पूर्व राजा ने नवराज सुवेदी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है जिसके भीतर सभी राजसंस्था समर्थक राजनीतिक दल, संघ संगठन, समूह को शामिल किया गया है। 28 मार्च को नेपाल के विपक्षी दलों का मोर्चा भी राजसंस्था के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी है।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने 8 अप्रैल को काठमांडू में आमसभा करने की घोषणा की है। इस आमसभा में काठमांडू और आसपास के 10 जिलों से लोगों को बुलाकर प्रदर्शन करने की जानकारी दी गई है।

राप्रपा के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि इस सभा के लिए पार्टी आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर आम लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील करने वाली है।

उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश के सभी प्रमुख शहरों में आमसभा, जुलूस प्रदर्शन और जिला प्रशासन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। इसके बाद 20 अप्रैल से काठमांडू केंद्रित आंदोलन को आगे बढ़ाने की राप्रपा की योजना है। धवल शमशेर राणा ने कहा कि 20 अप्रैल से काठमांडू हर दिन कोई न कोई आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है।

आंदोलन के आखिरी चरण में राजदरबार के भीतर जाकर वहां प्रदर्शन करने की बात कही गई है।

राणा ने बताया कि 24 अप्रैल को नारायणहिटी राजदरबार के आगे लाखों नेपाली जनता को उतारकर दरबार के भीतर राज को स्थापित करने की योजना है। 24 अप्रैल को ही तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने निरंकुश राजशाही के अंत की घोषणा करते हुए लोकतंत्र की पुनर्बहाली की घोषणा इसी दरबार से की थी। बाद में सरकार ने राजा ज्ञानेन्द्र और उनके पूरे परिवार को राजदरबार खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद ज्ञानेन्द्र शाह ने अपने परिवार सहित नारायणहिटी दरबार खाली कर दिया था।

वाशिंगटन में नेशनल इंटेलीजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड, सीआईए निदेशक जॉन रेटक्लीफ, एफबीआई निदेशक काश पटेल सीनेट समिति के सामने पेश हुए। ये तीनो केपिटल हिल को लेकर खतरे पर जबाव देने पहुंचे थे।

भारतीय निशानेबाजों का पहला दल अर्जेंटीना के लिए रवाना

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय निशानेबाजों का 22 सदस्यीय पहला दल बुधवार सुबह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो गया है। दल में 13 सहायक स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं। भारतीय निशानेबाज 2025 के पहले अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप (राइफल/पिस्टल/शॉटगन) में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, जिसकी प्रतिस्पधाएं 03 अप्रैल से शुरू होंगी। कुल 35 भारतीय निशानेबाज 15 पदक आयोजनों में भाग लेंगे, जिसमें 12 व्यक्तिगत और 03 मिश्रित टीम इवेंट्स शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर एकमात्र एथलीट हैं जिन्हें दो व्यक्तिगत इवेंट्स में चयनित किया गया है। शेष टीम के सदस्य 29 मार्च को रवाना होंगे, क्योंकि उनकी प्रतियोगिताएं टूर्नामेंट के बाद के चरणों में शुरू होती हैं। कुछ को छोड़कर सभी निशानेबाजों ने 14 मार्च से दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय रचनात्मकता शिविर में भाग लिया था, जो दक्षिण अमेरिका में होने वाले दोहरे वर्ल्ड कप चरण की तैयारी कर रहे थे। ब्यूनस आयर्स के बाद पेरू के लीमा में अगले महीने दूसरा वर्ल्ड कप होगा।

इससे पहले भारतीय निशानेबाजी टीम के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर रौनक पांडे ने शिविर की प्रमुखता के बारे में बात करते हुए कहा, हमारा मुख्य ध्यान हर एथलीट की क्षमता को अधिकतम बनाने पर है। इस बार हमारी कोचिंग टीम बड़ी है और नए युवा टैलेंट की भी काफी संख्या है, तो शुरूआती दिनों में सभी निशानेबाजों की ताकत और कमजोरियों को समझने का काम किया गया, ताकि हर एक के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

पहले दो वर्ल्ड कप चरणों के लिए भारतीय टीम युवाओं और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है, जिसमें 16 ओलंपियन, पूर्व विश्व चैंपियन, विश्व नंबर-1 और डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर शामिल हैं। हालांकि ध्यान युवा निशानेबाजों पर भी रहेगा जैसे कि सुरुचि, सैय्यम, आर्या बोरसे, सोनम मास्कर, नर्मदा नितिन, आशी चौकसे और भवतेग गिल, जो अपना पहला व्यक्तिगत आईएसएसएफ वर्ल्ड कप पदक जीतने के लिए तैयार होंगे।

गुज्जर और बक्करवालों के लिए अंतर-ग्राम वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित

रियासी, (हि.स.)। सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और खेल भावना को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास में भारतीय सेना ने बुधवार को जिला रियासी के बलमतकोट के सुदूर स्थान पर गुज्जर और बक्करवाल समुदाय के लिए अंतर-ग्राम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में कई गांवों से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जिसमें युवा एथलीटों ने अपनी प्रतिभा, टीमवर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया।

अब्यूनस आयर्स में विश्वकप फुटबॉल क्वालिफायर में खेलते हुए फुटबॉलर।

जॉर्डन में सीनियर एशियन कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत के ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता।

महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, निदा डार बाहर

नई दिल्ली, (हि.स.)। पाकिस्तान ने आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 क्वालिफायर के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 9 से 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में खेला जाएगा, जिसमें मेजबान पाकिस्तान सहित छह टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट के शीर्ष दो स्थानों पर रहने वाली टीमें इस साल भारत में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी, जो पिछले साल आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भी पाकिस्तान की कप्तान रही थीं। हालांकि, टीम से बॉलिंग ऑलराउंडर निदा डार को बाहर रखा गया है। निदा उन 19 खिलाड़ियों में शामिल थीं, जिन्हें इस क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया था, लेकिन अंतिम टीम में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। इस टीम में युवा बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार की भी वापसी हुई है, जो 2023 में कंधे की चोट के कारण क्रिकेट से दूर रही थीं। यह छह टीमों का क्वालिफायर टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी। शीर्ष दो टीमें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो इस साल भारत में होगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। फातिमा सना (कप्तान), नाजीहा अल्वी, गुल फिरोजा, सिद्रा अमीन, ओमैमा सोहेल, आलिया रियाज, डायना बेग, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, मुनीबा अली, रमीम शमीम, शवाल जुल्फिकार, सैयदा अरूब शाह, नतालिया परवेज, सिद्रा नवाज। आयरलैंडः गाबी लुईस (कप्तान), अवा कैनिंग, क्रिस्टिना कूल्टर, अलाना डालजेल, लॉरा डेलानी, सारा फोर्ब्स, एमी हंटर, अर्लेन केली, लुइस लिटिल, सोफी मैकमोहन, जेन मैगुआयर, किआ मैकार्टनी, कारा मरे, लिया पॉल, ऑर्ला प्रेंडरगास्ट (उप-कप्तान)। स्कॉटलैंडः कैथरीन ब्राइस (कप्तान), क्लोए एबल, अब्बी ऐटकेन-ड्रमंड, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), डार्सी कार्टर, प्रियनाज चटर्जी, कैथरीन फ्रेजर, एल्सा लिस्टर (विकेटकीपर), अब्ताहा मकसूद, मेगन मैककॉल, हन्ना रेनी, नायमा शेख, रैचल स्लेटर, पिप्पा स्प्रूल, एलेन वॉटसन (विकेटकीपर)।

वेस्टइंडीजः हेली मैथ्यूज (कप्तान), शमाइन कैंपबेल, आलिया अल्लेने, अफी फ्लेचर, चेरी एन फ्रेजर, शबिका गजनबी, जनीलिया ग्लासगो, चिनले हेनरी, जैदा जेम्स, कियाना जोसेफ, मैंडी मंगरु, अश्मिनी मुनिसार, करिश्मा रामहरक, स्टेफनी टेलर, राशादा विलियम्स।

बांग्लादेशः निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर, इश्मा तंजिम, दिलारा अख्तर, शार्मिन अख्तर सुप्ता, सोभना मोस्तरी, शॉर्ना अख्तर, जननतुल फर्दौस सुमोना, राबेया, फहीमा खातून, फरिहा इस्लाम तृष्णा, फरजाना हक, शांजीदा अख्तर मघला, मरुफा अख्तर, ऋतू मोनी।

स्टीलर्स और पिंक कब्स की बड़ी जीत, युवा पलटन ने बनाए रखी उम्मीदें

हरिद्वार, (हि.स.)। वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में जारी युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप में बुधवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें जूनियर स्टीलर्स, जयपुर पिंक कब्स, युवा पलटन और पलानी टस्कर्स ने शानदार जीत दर्ज की।

दिन के पहले मुकाबले में जूनियर स्टीलर्स ने वास्को वाइपर्स को 63-26 से हराया। पहले हाफ में स्टीलर्स ने दो ऑल-आउट और एक सुपर रेड के दम पर 32-12 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में उन्होंने दो और ऑल-आउट कर मुकाबले को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया। जया सूर्या 18 अंकों के साथ मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। स्टीलर्स अब 33 अंकों के साथ पूल ए में चौथे स्थान पर हैं, जबकि वाइपर्स 14 अंकों के साथ अंतिम पायदान पर हैं। दूसरे मुकाबले में जयपुर पिंक कब्स ने यूपी फाल्कन्स को 50-33 के बड़े अंतर से हराया। पहले हाफ तक कब्स ने 27-15 की बढ़त बना ली थी। मैच के दौरान परविंदर ने 16 अंक और के. धरनीधरन ने 13 अंक जुटाए।

दिल्ली

छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं निजी स्कूल : आशीष सूद

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों पर यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य लेखन सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालने और छात्रों से पैसे वसूलने की शिकायत मिलने पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सभी निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी दी। मंत्री ने बताया कि छात्रों और उनके माता-पिता से मिली शिकायतों को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 24 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी स्कूलों को सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए निजी स्कूल मजबूर नहीं कर सकते हैं।

आशीष सूद ने बताया कि निजी स्कूलों को निर्देश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार को छात्रों से यूनिफॉर्म और किताबें किसी विशेष दुकानदार से खरीदने के लिए बाध्य करने की कई शिकायतें मिल रही थी। कई निजी स्कूल बच्चों को जरूरी सामान देने के लिए अभिभावकों से पैसे की भी मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसी हर गतिविधि को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान हैं।

छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें और जरूरी सामग्री की शिकायत मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। स्कूलों को साफ चेतावनी दे दी गई है कि कानून का पालन नहीं करने पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, नियम 1973 और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय को सभी जिला और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइंस की निगरानी के साथ ही अभिभावकों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत का तुरंत समाधान करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा-निर्देशों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। अभिवावकों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक मनीष जैन उप शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर - 9818154069 और ईमेल आईडी -- ïïï३1@’ .ङ्क्ष भी जारी किया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर बच्चे को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने संकल्प पर अडिग है। अगर कोई स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे ओर सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 9 बिंदुओं की एक दिशा-निर्दश जारी किया गया है। इसका दिल्ली के सभी निडी स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा।

महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने सहकर्मी प्रोफेसर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

नई दिल्ली, (हि.स.)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने सहकर्मी प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित प्रोफेसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित प्रोफेसर मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ एक महिला सहयोगी ने दुष्कर्म की शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों मई 2024 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

मानसून सत्र को ई विधानसभा के रूप में आयोजित करने का प्रयास : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, (हि.स.)। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को दिल्ली विधानसभा को ई-विधानसभा बनाने के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वह 100 दिन के भीतर ई-विधानसभा को लागू करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि मानसून सत्र ई-विधानसभा एप्लीकेशन 'नेवा' का उपयोग करके आयोजित किया जा सके।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 22 मार्च को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का पूरा फंड केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ई-विधानसभा परियोजना से सदन की कार्रवाई ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि अब सदस्यों को अपने नोटिस ऑनलाइन जमा करने और अपने फोन या टैबलेट पर विधानसभा के सभी रिकॉर्ड प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह एप्लीकेशन न केवल विधानसभा से संबंधित कार्यों जैसे प्रश्न, कार्य सूची, चचाएं, विधायी कार्य और समिति कार्यों में मददगार होगी, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के प्रबंधन में भी उपयोगी साबित होगी।

गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय में एक स्थायी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां सदस्यों को एप्लीकेशन के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह एप्लीकेशन टचस्क्रीन डेस्कटॉप पर भी उपलब्ध होगी, जिसे प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगाया जाएगा और इसे टैबलेट या मोबाइल डिवाइस पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वन नेशन-वन एप्लीकेशन संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी विभागों से इस नई तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।

पांच लोगों की हत्या के मामले में 14 साल से फरार सजायाफ्ता पैरोल जम्पर गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 साल के सजायाफ्ता पैरोल जम्पर राजकुमार उर्फ राजूजो को 14 साल के बाद गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि वह 2011 में 40 दिनों के लिए पैरोल पर आया था और फिर फरार हो गया। उसने

छह जुलाई 1996 में अपने तीन सहयोगियों के साथ लूट के लिए एक रिश्तेदार के घर में प्रवेश किया और लूट का विरोध करने पर पांच लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद वे लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपित को एक गुप्त सूचना के आधार पर मुल्तान नगर मेरठ से गिरफ्तार किया।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि वह हापुड़ का रहने वाला है। उसके 1990 से 1996 तक मेरठ के सदर बाजार में बैग बनाने का काम किया। वर्ष 1996 में उसके दोस्त राजेंद्र ने एक जानकारी साझा की कि भजनपुरा दिल्ली में रहने वाले उसके चचेरे भाई ने अपनी संपत्ति 22 लाख रुपये में बेची है और सारा पैसा उसके घर में रखा है। इसके बाद उसने अपने साथी राजेंद्र उर्फ राजू, सुनील, जयकिशन के साथ मिलकर राजेंद्र के चचेरे भाई को लूटने की साजिश रची। रात में सभी लोग घर पहुंचे। लूटपाट का विरोध करने पर उन्होंने राजेंद्र के चचेरे भाई को चाकू घोप दिया। उसके बाद उन्होंने घर में मौजूद महिला (मृतक की साली) के साथ दुष्कर्म किया और बच्चों सहित पूरे परिवार को मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।डीसीपी के अनुसार मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर पांच शव मिले। उक्त मामले में राजेंद्र उर्फ राजू, सुनील, राजकुमार उर्फ राजू, जयकिशन, कवलजीत उर्फ कवल सिंह और राज रानी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान चार आरोपितों को 20 साल की सजा सुनाई गई। उनमें दो आरोपित सुनील और जयकिशन की सजा की अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी। इधर पकड़ा गया आरोपित राजकुमार उर्फ राजूजो वर्ष 2011 में पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया।

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

हैदरपुर फ्लाईओवर पर आवारा पशुओं के आने से रुका सीएम का काफिला

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले को शालीमार बाग के हैदरपुर फ्लाईओवर पर आवारा पशुओं के आ जाने की वजह से बुधवार को रुकना पड़ा। मुख्यमंत्री ने गाड़ी से उतर कर संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर पर घूम रहे आवारा पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल खोजने का निर्देश दिया।

दिल्ली की सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने की वजह से अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट में दिल्ली के गांव घुमनहेड़ा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 'मॉडल गौशाला' स्थापित करने के लिए 40 रुपए करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इस गौशाला में गौ-संरक्षण, दुग्ध उत्पादन और पशु चिकित्सा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है : संतोष कुमार सिंह

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डेन) में आयोजित त्रिदिवसीय मेले में दूसरे दिन मेले के कार्यक्रम का शुभारम्भ एमएलसी सन्तोष कुमार सिंह ने दीप प्रज्जलन कर किया।

एमएलसी सन्तोष कुमार सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वन्दना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने एमएलसी का स्वागत किया। महाकुम्भ 2025 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित लघु फिल्म का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। एमएलसी सन्तोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 8 वर्ष पूर्ण होने पर त्रिदिवसीय मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में जनसामान्य को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जनसामान्य लाभ भी प्राप्त कर रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के समस्त वर्गो को योजनाओं का लाभ एवं नौकरियॉ दी जा रही है। विभिन्न विभागों में आटउसोर्सिंग पर रखे गये कर्मचारियों हेतु निगम बनाया जा रहा है जिससे अब सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंचेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नही होगी। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा 7 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियॉ दी गयी। प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना की जा चुकी है और जो भी अवशेष जिले है वहां पर मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी। महाकुम्भ से सामाजिक मजबूती तो मिली ही है, लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण भी हुआ है और इसके आस-पास के जनपदों को भी लाभ मिला है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई है, महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नम्बर एक राज्य है। प्रदेश में पहले भूमाफिया हाबी रहते थे लेकिन जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आयी तब से भूमाफिया गायब हो चुके है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गयी है और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये है। प्रदेश 8 साल में उन्नतिशील, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश बना है। विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आदित्य प्रंजापति, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, भाजपा मीडिया प्रभारी राघवेन्द्र शुक्ल सहित भाजपा के राजेश सिंह, विक्रम प्रताप सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारीगण व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री के लिए सरकार ने डिग्री की अनिवार्यता नहीं रखी : हाई कोर्ट

- **मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और इंटर के आधार पर तैयार की जानी चाहिए**

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या परास्नातक की डिग्री होना अप्रासंगिक है। न्यायालय ने कहा कि मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, न कि स्नातक और परास्नातक डिग्री के आधार पर।

याची चांदनी पान्डेय ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उसकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी गयी क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री अपलोड नहीं कर सकी थी।

न्यायालय के प्रश्न पर याचिकाकर्ता के वकील ने 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश की धारा 7 दिखाई, जिसमें प्रावधान है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर तैयार की जाएगी।

अदालत ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता, जब उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किए गए हैं।

न्यायालय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री के लिए मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता अर्थात हाईस्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, न कि उम्मीदवारों की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर।

संभल में सड़कों-छतों पर नहीं पढ़ सकेंगे जुमा अलविदा और ईद की नमाज।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को बीस वर्ष की जेल

दिव्य भारत संवाददाता

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारूल वर्मा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने के आरोप में राम लखन उर्फ सुग्गू थाना लालगंज को दोषी पातें हुये 20 वर्ष के कारावास तथा 35 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की। वादिनी मुकदमा के अनुसार उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 14 वर्ष कक्षा 7 की छात्रा थी उसकी पुत्री के साथ घटना 19 अप्रैल 2016 के दो माह पूर्व राम लखन ने उसके घर में आकर उसकी अनुपस्थिति में जबरन शारीरिक संबंध बनाये। जाते समय उसकी पुत्री को धमकी दिया कि अगर किसी से बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। लगभग 15 दिनों पहले उपरोक्त राम लखन ने उसकी लड़की को कोई दवा लाकर दी जिसे खाने से उसकी लड़की की तबियत खराब हुई तो उसने पूछने पर पूरी घटना से उसे अवगत कराया।वादिनी लोक लाज के कारण से चुप रही लेकिन नाबालिग पुत्री को देखने पर बार-बार मन में घुटन होने लगी और उसे रहा नहीं गया तब थाने पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया। उक्त मामले में राज्य की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 10 प्रदर्शो को साबित कराया गया। पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि राम लखन मेरे घर आया जाया करता था मुझे अकेली पाकर उसने मेरा मुंह दबा दिया और मेरे साथ गलत काम किया। उसने धमकी दी कि अपनी मां से बताओगी तो तुम्हें मार दूंगा। जब मेरा पेट फूलने लगा तो उसे पता चला तब उसने मुझे थप्पड़ मार के दवा खिला दिया।

संक्षिप्त समाचार

ईद पर दी जा रही भाजपा की सौगात-ए-मोदी किट सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ : मायावती

लखनऊ, (हि.स.)। भाजपा ईद के मौके पर असहाय परिवारों को सौगात-ए-मोदी किट पहुंचा रही है। इस पर भी सियासत तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इसे राजनीतिक स्वार्थ बताया है। बसपा प्रमुख ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि भाजपा का ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक 'सौगात-ए-मोदी' के रूप में प्रधानमंत्री का यह प्रेम संदेश व भेंट पहुंचाने की घोषणा केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ हैं। जब मुस्लिम व बहुजन समाज जान-माल, मजहब की सुरक्षा को लेकर दुखी व चिन्तित तो इसका क्या लाभ? जबकि बेहतर होता, अगर भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारें मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के कुछ गरीब परिवारों को यह सौगात-ए-मोदी देने की बजाय, उनकी गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन आदि को दूर करने के लिए रोजगार की स्थायी व्यवस्था करती व उनकी सुरक्षा पर भी उचित ध्यान देती।

ईद की सेवइयां खिलानी हैं तो गुझिया भी खानी पड़ेगी : अनुज चौधरी

>एसडीएम ने कहा-ईद व जुमा की नमाज नहीं होगी सड़क पर

संभल, (हि.स.)। रमजान का आखिरी जुमा (अलविदा) की नमाज, ईद और रामनवमी को लेकर क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी ने बुधवार को कोतवाली में पीस कमेटी के पदाधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि आपको ईद की सेवइयां खिलानी हैं तो आपको होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। गड़बड़ तब हो जाती है, जब एक पक्ष खा रहा है और दूसरा खाने को तैयार नहीं है। तब ये भाईचारा खत्म हो जाता है। मन में कड़वाहट लेकर आप भाईचारे की बात नहीं कर सकते। उन्होंने जुमा अलविदा, ईद और रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि जुमा अलविदा और ईद आपकी बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह से रामनवमी भी है। सभी त्योहार बहुत अच्छे से कराने हैं। शासन का निर्देश रहता है कि सभी त्योहार शातिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करायें और हम पूरी तरह से आदेश का पालन करते हैं।

राहुल गांधी का कोई विजन नही हैं, वह छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं : बृजेश पाठक

कानपुर, (हि.स.)। विपक्ष केवल जाति और धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है। उनका अभी भी इटली का मोह नहीं छूट रहा है। शायद इसीलिए वह छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर चले जाते हैं। प्रयागराज में इतना भव्य महाकुंभ का सफलतापूर्वक हुए आयोजन को लेकर विपक्ष परेशान है। अखिलेश यादव के पेट में सत्ता हासिल करने का कीड़ा है। यह बातें बुधवार को उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कही। प्रदेश में योगी सरकार को आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक शहर पहुंचे। जहांबीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के आठ वर्षों के सफर को पूरा होने पर बधाई दी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है।

राणा सांगा की वीरता और देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं: अखिलेश यादव

लखनऊ, (हि.स.)। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर हुए हमले के बाद अखिलेश यादव एक तरह से बैकफुट पर दिखाई दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार पर भी सवाल दागा। कहा कि् क्या पीडीए सांसद पर इस तरह का हमला जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत आएगा। ऐसा करने वालों की एआई से पहचान कर दंडित किए जाए। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को कहा था कि भारत में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहीम लोदी पर हमला करने को बुलाया था। इस बयान के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सांसद के आगरा स्थित पर हमला कर दिया। इसके बाद सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गये इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राज-काज के निर्णय अपने समय की परिस्थियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे।

कैश कांड के आरोपी जज स्वीकार नहीं

- **इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी, गुरुवार को भी वकीलों का कार्य बहिष्कार–इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी, गुरुवार को भी वकीलों का कार्य बहिष्कार**

प्रयागराज, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरण किये जाने के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य न करते हुए स्थानांतरण का विरोध करते हुए नए जजों की नियुक्ति करने की मांग दोहराई। अधिवक्ताओं के कार्य न करने से अदालतों में कामकाज नहीं हो सका। न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही।

इसके पूर्व अधिवक्ताओं ने सुबह कोर्ट का समय शुरू होते ही अपना विरोध शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट में जजों की कमी है। नए जजों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। जजों की कमी से मुकदमों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है।

हाईकोर्ट में लिस्टिंग सहित कई अन्य तकनीकी और व्यावहारिक परेशानियों से अव्यवस्था हावी हो गई है। अधिवक्ता अपने मुवक्किल को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाईकोर्ट में अंकल जज का सिंड्रोम हावी है। इन मुद्दों पर विचार करने की बजाय कैश कांड के आरोपी जज को यहां भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को यह बर्दाश्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने ऐसा कर न केवल हाईकोर्ट की गरिमा पर न केवल कुठाराघात किया बल्कि जस्टिस वर्मा को उनके पैतृक न्यायालय भेजकर उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया है। सभी अधिवक्ता एक स्वर में इसका विरोध करते हैं। हाईकोर्ट के गेट नंबर तीन पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने जस्टिस यशवंत वर्मा के स्थानांतरण को रद्द करने, लिस्टिंग की नई व्यवस्था में परिवर्तन कर पहले से दाखिल मुकदमों पर पहले सुनवाई करने सहित कुल आठ मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया। साथ ही उन अधिवक्ताओं को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया है, जो हड़ताल के इस दौरान न्यायालयों में न्यायिक कार्य किए। ऐसे अधिवक्ताओं को दो दिन में अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

इस दौरान आंदोलन को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। महासचिव विक्रांत पाण्डेय ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक बैठक बृहस्पतिवार को दो बजे बुलाई गई है। उसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खरे, पूर्व अध्यक्ष इन्द्र कुमार चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह, डॉ. सीपी उपाध्याय, एसी तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, प्रशांत सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अखिलेश कुमार मिश्र, सुभाष चंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी के और अन्य अधिवक्ताओं ने सभा को सम्बोधित किया।

कानून मंत्री से हुई सकारात्मक वाताहाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद स्थानांतरण के मामले में उनकी वार्ता कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ हुई है। उनकी बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है। सम्भावना है कि परिणाम बार की मांगों के अनुरूप होगा।

एडीजी जोन द्वारा कर्मचारियों को किया गया सम्मानित

- **एडीजी जोन ने ग्राम प्रहरियों को दी साइकिल और टार्च**
- **महाकुम्भ मेला में सराहनीय कार्य के लिये कर्मचारियों को किया गया सम्मानित**

दिव्य भारत संवाददाता

प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूरे होने पर रिजर्व पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज भानु भाष्कर, आईजी प्रयागराज रेंज प्रेम गौतम को पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में गार्द द्वारा सलामी दी गयी।

वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार और अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत एवं अभिवादन किया गया। उसके बाद जिले भर के 267 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, टार्च, परिचय पत्र का वितरण किया गया और उनके कर्तव्यों, दायित्वों के बारे में अवगत कराया।

साइकिल, टार्च, परिचय पत्र पाने के बाद ग्राम प्रहरियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। एडीजी जोन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ग्राम प्रहरियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। वहीं महाकुम्भ मेला-2025 के सफल तरीके से समापन के बाद एडीजी जोन भानु भास्कर के द्वारा महाकुम्भ मेला में सराहनीय एवं प्रभावशाली कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को महाकुम्भ मेला प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और उन्हें बधाई भी दी गई।

महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी का विरोध सपा सांसद के खिलाफ अधिवक्ताओं ने द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

अजीत प्रताप सिंह

प्रतापगढ़। अधिवक्ता समाज ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। सभी की उपस्थिति में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 22 मार्च को संसद में सपा सांसद ने महाराणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उन्हें गद्दार कहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि महाराणा सांगा की राष्ट्रभक्ति मेवाड़ के जन-जन में बसी है। इस तरह की बयानबाजी से न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे देश का हिंदू समाज आहत है।

प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता समाप्त करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसमें मुख्य रूप से मुक्तेश्वर ओझा मुक्कू, अंजनी सिंह बाबा, दिवाकर सिंह, विक्रम सिंह, संदीप तिवारी राजन, निशांत यादव, अनुराग सिंह, आशीष श्रीवास्तव, विजय सिंह सोलंकी, अजय सिंह अज्जू, गौरव सिंह, अभिनव मिश्र, अनुज सिंह आदि अधिवक्तागण मौजूद रहें।